झारखण्ड की समृद्धि का संकल्प

भारतीय जनता पार्टी, झारखण्ड प्रदेश

झारखण्ड पुकारा
भाजपा दोबारा

अनुक्रमणिका

1 मुख्यमंत्री का संदेश ____ 6

2 विकास के पांच वर्ष ____ 8

3 कृषि और किसान कल्याण ____ 13

4 जनजातीय विकास का संकल्प ____ 19

5 सशक्त युवा - समृद्ध प्रदेश ____ 23

6 महिला एवं बाल विकास ____ 27

7 सबका साथ - सबका विकास ____ 31

8 अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास ____ 36

9 झारखण्ड में विकास की नींव ____ 39

10 सुशासित प्रदेश - सुरक्षित प्रदेश ____ 44

11 स्वस्थ झारखण्ड ____ 47

12 शिक्षित झारखण्ड,विकसित झारखण्ड ____ 50

13 हमारी संस्कृति और धरोहर ____ 54

14 पर्यटन विकास ____ 57

15 वन और पर्यावरण संरक्षण ____ 61

झारखण्ड की समृद्धि का संकल्प

जोहार!

मेरे प्यारे झारखण्डवासियों,

प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य को अपने में समेटे झारखण्ड की संस्कृति की हमेशा से अलग पहचान रही है। यहां बाबा बैद्यनाथ, मां छिन्नमस्तिका, भद्रकाली, पारसनाथ (पार्श्वनाथ), लुगूबुरु घंटा बाड़ी जैसे धार्मिक स्थल हैं, तो दूसरी ओर कोयल, दामोदर, स्वर्णरिखा जैसी कलकल बहती नदियों का सौंदर्य, स्वयं अपनी गाथा बयॉ करती है। झारखण्ड को प्रकृति ने प्रचुर खनिज संपदा से नवाज़ा है। जल, जंगल और जमीन केवल एक नारा नहीं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती - झारखण्ड की अमानत और पहचान है। इन सभी प्राकृतिक संपदाओं और संसाधनों से धनवान होने के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के कारण झारखण्ड का समग्र विकास नहीं हो पाया था। 14 वर्षों तक खंडित जनादेश के कारण जिस उम्मीद से अलग राज्य का गठन हुआ था वह पूरा नहीं हो पाया।

28 दिसंबर, 2014 को झारखण्ड ने नई विकास यात्रा शुरू की थी। सालों की बेरोजगारी, गरीबी और लाचारी से झारखण्ड के जन-जन का मन थका चुका था। पूरे प्रदेश में निराशा का भाव था। लेकिन, हमने इसे चुनौती के तौर पर लिया। हमने दृढ़ संकल्प लिया था कि हमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है और झारखण्ड को विकास के पथ पर सरपट दौड़ाना है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार ने झारखण्ड की जनता के साथ मिलकर हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर हमने झारखण्ड के माथे से भ्रष्टाचार का कलंक मिटा दिया है। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों में फिर से आत्मविश्वास जगाया कि अस्थिरता के काले बादल अब छंट गए है और लूट एवं परिवारवाद की राजनीति का अंत हो गया है।

पिछले पांच साल का हमारा स्थिर कार्यकाल, इस बात का साक्षी है कि कैसे झारखण्ड की विकास यात्रा, जन-आंदोलन का रूप ले सकती है। आज, हर प्रदेशवासी गर्व से कहता है कि हां, मैं झारखण्डवासी हूँ। प्रदेश में, समृद्धि लौट रही है, रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं, देश-दुनिया में झारखण्ड तेजी से विकास करने वाले प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, रोजगार एवं ग्रामीण विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने आमजन की पीड़ा को समझा और अनुभव किया है। इसलिए, गरीब, बेरोजगार, दिव्यांग, विधवा, महिलाएं, शोषित एवं वंचित वर्ग , हमारी प्राथमिकताओं के केंद्र में रहे हैं। साथ ही, सुशासन एवं सुलभ न्याय भी हमारा लक्ष्य है। हमने 5 वर्षों में खुद को इनकी सेवाओं में समर्पित किया है। पंडित दीनदयाल के अन्त्योदय के सिद्धांत को आधार मानकर एवं माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, हमने सारी सुविधाएं वंचितों के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया है।

मुझे, यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी स्थिर सरकार के कार्यकाल में झारखण्ड में हर क्षेत्र और हर वर्ग का अतुलनीय विकास हुआ है। आज झारखण्ड Ease of Doing Business में देश में चौथे स्थान पर है। 546 नयी औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास हुआ है, जिससे 71,000 करोड़ का निवेश झारखण्ड को प्राप्त होगा। पांच वर्षों में जहाँ 22,865 कि.मी. सड़कों का निर्माण हुआ है, वहीं झारखण्ड शीघ्र ही अपनी मांग से अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करेगा। विगत पांच वर्षों में, प्रदेश की कृषि विकास दर में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से प्रदेश के 30 लाख से भी अधिक लघु और सीमांत किसानों को 25,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आज, झारखण्ड देश में नीली क्रांति के क्षेत्र में अग्रणी है।

हमारी सरकार ने अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के संकल्प को निभाया है। पहली बार झारखण्ड को अलग प्रदेश बनाने के संग्राम में शामिल वीरों को सरकार पेंशन और प्रशस्ति पत्र देकर, उन्हें सम्मानित कर रही है। आदिवासी ग्राम सभाओं के माध्यम से गाँव-गाँव में 5 लाख तक के विकास कार्य किए जा रहे हैं। अपने जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षण हेतु जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण को गैर-कानूनी बनाया है और इसके खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया है।

महिला सशक्तिकरण के लिए हमने जो कार्य किया, वो पूरे देश के लिए मिसाल है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से जहाँ प्रदेश की लाखों बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं, वहीं 2 लाख 17 हज़ार सखी मंडलों ने प्रदेश में महिला उद्यमिता को एक नयी दिशा दी है। हमारी सरकार ने देश में पहली बार 40 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा और दो सिलेंडर का रिफिल भी मुफ्त प्रदान किया है। युवाओं का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पहली बार प्रदेश में एक सशक्त नीति बनाकर, प्रदेश में वर्ग 3 और 4 की नियुक्तिओं को केवल हमारे झारखण्ड के युवाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। विगत 5 वर्षों में, जहाँ एक ओर कौशल विकास के माध्यम से 32 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं, वहीं 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।

झारखण्ड में दशकों बाद अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। पिछले पांच वर्षों में, हमने देवघर में एम्स (AIIMS) और प्रदेश में अन्य 5 चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया हैं। आयुष्मान भारत के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, 108 एम्बुलेंस की सुविधा, अटल मोहल्ला क्लिनिक, कम दर पर दवाइयां और ऐसे कई क़दमों से यह सुनिश्चित किया है कि झारखण्ड में हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ पहुचें। आज, प्रदेश में नागरिकों को पक्का मकान, पेयजल, बिजली, शौचालय आदि की सुविधा प्रदान की गई है। गरीबी उन्मूलन के हमारे इन प्रयासों को न केवल देश में बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ (UNDP) द्वारा भी सराहा गया है। नक्सलवाद झारखण्ड के विकास में एक बड़ी बाधा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नक्लसवाद पर करारा प्रहार किया है। दिन हो या रात आज झारखण्ड के किसी भी कोने में निर्भीक हो कर यात्रा की जा सकती है। हमारी सरकार की पारदर्शी और कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं ने देश-दुनिया में मिसाल कायम की है।

इस बार विधानसभा चुनाव, झारखण्ड की विकास यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अगले 5 वर्षों के लिए प्रदेश को अगली पंक्ति में खड़ा करने के वाहक हैं। आप स्वयं हमारे कार्यों का मूल्यांकन करें। विगत 5 वर्षों में ईमानदार, ठोस और बहुआयामी प्रगति लाने वाला स्थिर और पारदर्शी सुशासन, हमने दिया है। वर्तमान सरकार आने वाले दिनों में विकास और प्रदेश की समेकित समृद्धि की बड़ी लकीर खींचने की पक्षधर है। इसलिए, आज भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार आपका आशीर्वाद लेने आई है। झारखण्ड की विकास यात्रा को हम बिना रुके, बिना थके, यूं ही जारी रख सकें, इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद और स्नेह चाहिए।

जय हिन्द, जय झारखण्ड !

!!सबका साथ- सबका विकास- सबका विश्वास!!

रघुवर दास
मुख्यमंत्री

विकास के 5 वर्ष

01 अर्थव्यवस्था

पांच वर्षों में 546 नई औद्योगिक इकाइयां और 71,000 करोड़ का निवेश

02 स्वास्थ्य

57 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रूपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा

03 रोज़गार

अलग-अलग माध्यमों से 32 लाख युवाओं को रोजगार

04 आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख से अधिक शहरी एवं 4.68 लाख ग्रामीण घरों का निर्माण

05 महिला

40 लाख महिलाओं तक उज्ज्वला योजना का लाभ पहुंचा। चूल्हा, पहला और दूसरा रिफिल मुफ्त मिला

विकास के 5 वर्ष

01 जनजातीय कल्याण

2014 तक जहां राज्य का जनजातीय बजट 11 हजार 997 करोड़ था वह लगभग अब दोगुना बढ़कर 20 हजार 664 करोड़ हो चुका है। पहली बार जनजातीय गांव के सर्वांगीण विकास के लिए, आदिवासी विकास समिति के माध्यम से 5 लाख रुपये दिए गए हैं। इसी प्रकार जनजातीय प्रतिभा संपन्न युवाओं को सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री डाकिया योजना के तहत निःशुल्क 35 किलो खाद्यान प्रत्येक माह 73,386 आदिम जनजाति परिवारों को उनके द्वार पर पहुंचाया जा रहा है। इसी पांच वर्ष की अवधि में 61,970 वनाधिकार पट्टा प्रदान किए गए हैं।

हमारी सरकार द्वारा जनजातीय संस्कृति एवं परंपरा की सतत समृद्धि की दिशा में मानकी को 3,000 रुपये, मुंडा और ग्राम प्रधान को 2,000 रुपये तथा डाकुआ को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त परगनैत, पराणिक, जोगमाझी, कुणाम, नाइकी, गुणैत, मूलरैयत, पणहा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को प्रतिमाह 1,000 रुपये सम्मान की स्वीकृति दी गई है। जनजातीय परंपरा में टाना भगतों की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार ने टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन, रांची में अतिथि गृह का निर्माण तथा 335 टाना भगतों को निःशुल्क गायों का वितरण किया गया है।

02 सांस्कृतिक एवं भाषाई समृद्धि की ओर

बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास, रांची को उन्नत संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है एवं भगवान बिरसा मुंडा की 25 फिट ऊंची आदमकद मूर्ति स्थापित की जा रही है। जनजातीय सांस्कृतिक समुन्नति एवं भाषाई संरक्षण के क्रम में हमारी सरकार ने वृहद कदम उठाए हैं। 521 जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र, माझी- मानकी हाऊस, धुमकुड़िया केंद्र का निर्माण कराया गया है। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु 1,597 सरना मसना जाहेर स्थान हड़गड़ी की घेरा बंदी की गयी है। संथाली ओलचिकी लिपि को मान्यता देते हुए इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है।

03 समग्र समाज कल्याण

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में मिल रहे प्रोत्साहन राशि और कन्यादान योजना से लाखों परिवार जहां शिक्षा से जुड़ रहे हैं। अंबेडकर आवास योजना के तहत विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए 10 हजार से अधिक आवास का निर्माण हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 20,88,126 विधावाओं, वृद्धों, दिव्यांगों आदि की पेंशन राशि को 600 से बढ़ाकर 1,000 कर दिया गया है। राज्य में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन तथा आदिम जनजाति समुदाय के लिए दो पहाड़िया बटालियन का गठन भी किया गया है।

04 उत्तरोत्तर शैक्षिक विकास

इस अल्प अवधि में 31,438 स्कूलों में बैंच और डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं, तो 27,885 विद्यालयों तक बिजली पहुँचाई गई है। राज्य में ड्रॉप आउट शून्य पर आ गया है। हमारी सरकार ने 13 पॉलिटेक्निक स्थापित किए हैं जिसके परिणामस्वरूप आज सीटों की संख्या बढ़कर 11,575 हो गई है। इसी अवधि में 5 नए सरकारी विश्वविद्यालय तथा 11 निजी विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं। आज हमारे 6000 बच्चे विगत दो वर्षों में निःशुल्क देश भ्रमण कर चुके हैं। राज्य में 52 नए महाविद्यालय तथा 25 नए एकलव्य विद्यालयों कि स्थापना की गई है। आज राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को मुफ्त में यूनिफार्म, पुस्तक और साईकिल दी जा रही है।

05 ज्योतित झारखण्ड

4 साल में 68 लाख घरों तक बिजली पहुंची है तो 10 ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण हो चुका है एवं 60 ग्रिड सबस्टेशनों का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार 4,027 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के साथ-साथ 14,1976 कि.मी. लंबी विद्युत वितरण लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2022 में पतरातू पावर प्लांट से 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरु हो जाएगा। अब तक 3.28 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी है।

06 बेहतर अवसंरचना

पांच वर्षों की अवधि में जहां 22,865 कि.मी. सड़कें बनी हैं वहीं 131 उच्च स्तरीय पुल तथा मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 568 पुलों का निर्माण कराया गया है। 465 करोड़ की लागत से झारखण्ड विधानसभा भवन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा किया गया। 1,556 करोड़ की लागत से बनने वाले सचिवालय भवन का शिलान्यास हो चुका है। साहिबगंज में 290 करोड़ की लागत से जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है जो अंतर्राज्यीय/ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा रोज़गार को सुगम बनाएगा।

07 हर घर नल-हर घर जल

यद्यपि झारखण्ड में 1,300-1,400 मिमी वर्षा होती है परंतु पारिवेशिक कठिनाइयों के चलते प्रचुर मात्रा में जल संग्रहण में कठिनाई होती है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के आह्वान के आलोक में 4 साल में 8,044 गांवों को पाइपलाइन से जोड़ा है जिससे 32 प्रतिशत आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। झारखण्ड का स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान है। 40 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। 11,126 अनुसूचित जनजाति तथा 2,251 आदिम जनजाति टोलों के लिए शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु कार्य किया जा रहा है। आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित 483 टोलों में सतही जलापूर्ति योजना के तहत स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल सहिया बहनों को 1,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है।

08 अपार पर्यटन संभावनाएं

प्राचीन काल से ही झारखण्ड की सुरम्य वनस्थली, प्राकृतिक संरचना के साथ-साथ धार्मिक एवं धरोहर के कारण पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार ने पर्यटन को रोज़गार के साथ जोड़ने एवं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया है। परिणास्वरूप 2018 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 1.75 लाख अर्थात लगभग 2014 की तुलना में 13.6% की वृद्धि हुई है। 9,000 से अधिक श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत देश का भ्रमण कराया गया है। हमारी सरकार ने श्रावणी मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया है। स्थापत्य का दुर्लभ उदाहरण मलूटी, उधवा पक्षी विहार, फॉसिल्स पार्क, राजमहल के स्थापत्य, अंजन ग्राम, रामरेखा धाम, टांगी नाथ, नेत्तरहाट संथाल परगना के प्रमुख तीर्थ लुगुबुरु पहाड़ पर लगने वाला मेला, जनजातीय संस्कृति के विविध पर्व, बौद्ध संस्कृति के पदचिन्ह, बंशीधर मंदिर, भद्रकाली, छिन्नमस्तिका (राजरप्पा), देउड़ी के साथ-साथ विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थान पारसनाथ (पार्श्वनाथ) झारखण्ड की नैसर्गिक विशेषता है। इसी के साथ-साथ विभिन्न अभ्यारण्य मृग विहार और हाथियों के लिए प्रसिद्ध दलमा क्षेत्र सुप्रसिद्ध है।

09 रोज़गार सृजन एवं नियुक्तियां

4 साल में लगभग 32 लाख से ज्यादा रोज़गार एवं स्वरोजगार के अवसर युवा को प्राप्त हुए हैं। वहीं 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी गई है तथा 50 हजार नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। हमने 2.17 लाख सखी मंडलों के माध्यम से 26 लाख बहनों को स्वरोजगार से जोड़ा है। झारखण्ड में सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से भी 10 हजार लोगों को नौकरी मिली है तथा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से भी रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए हैं। झारखण्ड में महिला सशक्तिकरण के तहत 55 हजार रानी मिस्त्रियों को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर दिए गए हैं। 37 वर्षों के उपरांत लगभग 1,978 वनरक्षियों की नियुक्ति की गई है।

10 सुशासन हमारी प्राथमिकता

झारखण्ड इकलौता राज्य है जहां महिलाओं के नाम होने वाले भूमि, भवन का रजिस्ट्री फीस मात्र 1 रुपये है। इसके माध्यम से अब तक 1,83,624 से अधिक महिलाएं संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं। भूअभिलेखों का डिजिटलाइजेशन तथा पहली बार परंपरागत ग्राम प्रधान मानकी मुंडा आदि को राज्य सरकार द्वारा मानदेय दिया जा रहा है। मई 2015 से ही जन संवाद केंद्र का शुभारंभ हुआ जिसमें कुल प्राप्त 4 लाख शिकायतों में से 90 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया है।

11 कृषि आय दोगुनी करने का संकल्प

विगत पांच वर्षों में कृषि एवं संबद्ध सेवाओं में राज्य ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 24 महिला कृषकों समेत 95 कृषिकों को उन्नत कृषि अध्ययन हेतु इजराइल भेजा गया। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 16.14 लाख किसानों को इसके तहत आच्छादित किया गया है। इसमें किसान को 25 हज़ार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी गयी है। इसी के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत भी 14.39 लाख किसानों को तीन किश्तों में 6000 रुपये सीधे खाते में दिया गया है। मिट्टी के डॉक्टर की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। अब तक 17 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उपलब्ध कराया गया है। राज्य में 3,164 लघु मृदा जांच प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। हमारी सरकार ने चरणबद्ध रूप से 6,976 किसानों को मोबाइल फोन वितरित किया है ताकि उन्हें मौसम, कृषि, उत्पाद एवं बाजार का ज्ञान हो सके। इसी प्रसंग में 260 कृषि सिंगल विंडो भी स्थापित किये गए है।

12 विराट औद्योगिक परिसर झारखण्ड

प्रसंगाधीन अवधि में 546 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास हुआ है, जिसमें 71 हजार करोड़ के निवेश की संभावना है। 120 इकाईयां उत्पादन में आ गई हैं, 144 शीघ्र ही उत्पादन प्रारंभ करेंगी तथा शेष सभी प्रक्रियाधीन हैं। विकास को नई दिशा देने के लिए बोकारो, देवघर तथा धालभूमगढ़ अवस्थित हवाई अड्डों का विस्तारीकरण तेजी से किया जा रहा है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखण्ड 29 वें से अब चौथे स्थान पर आ गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रांची, ग्लोबल एग्रिकल्चर एवं फुड समिट रांची, वेंडर समिट जमशेदपुर, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वेंडर मीट बोकारो एवं बम्बू आर्टिजन कॉन्क्लेव दुमका के माध्यम से बड़े पैमाने पर उद्यम, उद्यमिता एवं स्वरोजगार की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

13 हरित वनभूमि एवं पर्यावरण

भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 530 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है। जो सकल वन क्षेत्र का 2.25 प्रतिशत है। यहां 33.21 प्रतिशत वनक्षेत्र हैं। इसी प्रकार ग्रोइंग स्टॉक भी उक्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 14 प्रतिशत की वृद्धि रेखांकित की गई है। मुख्यमंत्री जनवन योजना के तहत भी अब तक 6.60 लाख पौधे लगाए गए हैं।

14 समेकित विकास

झारखण्ड बड़ी तेजी से विकास में आगे आया है। गरीबी के बहुआयामी सूचकांक में बड़ी तेजी से कमी हुई है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड में अन्य राज्यों की तुलना में गरीबी तेजी से कम हुई है। गरीबी की व्यापकता 4.8 प्रतिशत एवं गहनता 2.4 प्रतिशत वार्षिक की दर से कम हुई है। वानिकी एवं मत्स्य पालन में औसत वृद्धि क्रमशः 31.2 और 15.39 रही है। राज्य सरकार के बेहतर आर्थिक प्रबंधन के चलते कई मानकों में वृद्धि हुई है।

15 सिंचाई तेज प्रगति की ओर

2015 में जहां वृहद एवं मध्यम सिंचाई परिक्षेत्र में कुल वास्तविक सिंचाई 91,323 हेक्टेयर थी, वह बढ़कर मार्च 2019 में 2,10.720 हेक्टेयर हो गई है। सरकार जहां वृहद सिंचाई योजनाओं को सुदृढ़िकरण के माध्यम से सिंचाई के लिए उपयुक्त बनाने में जुटी है। उसी के साथ स्वर्ण रेखा जैसी बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पूरा कराया जा रहा है। हमारी सरकार ने प्रदेश में वर्षों से लंबित पड़ी सिंचाई योजनाएं जैसे कोनार सिंचाई परियोजना, उत्तर कोयल परियोजना, कनहर बराज परियोजना एवं पुनासी जलाशय योजना को शुरू किया है। लघु सिंचाई परिक्षेत्र में 1,349 चेक डैम तथा 932 माध्यम सिंचाई योजना, आहर, तालाब इत्यादि का पुर्नस्थापन एवं सुदृढ़िकरण किया गया है।

कृषि और किसान कल्याण

किसान की दोगुनी आय

- हम मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का विस्तार कर झारखण्ड के अधिक से अधिक किसानों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे।
- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लागत मूल्य आधारित एमएसपी (न्यूनतम समर्थन दर) का भुगतान समयबद्ध रूप से एक सप्ताह में किया जाए:
  - इस पहल के लिए मुख्यमंत्री जन संवाद योजना के तहत एक अलग शिकायत प्रकोष्ठ का निर्माण करेंगे
  - भाजपा सरकार द्वारा धान की एमएसपी (MSP) पर दिए जाने वाले बोनस को 150 रुपये से बढ़ाकर 185 रुपये किया गया है। हम किसानों के कल्याण के लिए, इस कल्याणकारी कदम का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे
- हम ई-नाम (e-NAM) में पंजीकरण करने वाले सभी किसानों को मोबाइल फोन प्रदान करेंगे। इस कदम से प्रदेश के किसान को कृषि या किसान कल्याण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी बिना विलंब के सही समय पर प्राप्त होगी, साथ ही उन्हें अपने उत्पाद का सही मूल्य तय कर उसे राष्ट्रीय स्तर के बाजार में बिक्री करने का अवसर प्राप्त होगा।
- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक किसान को कृषि के लिए वित्तीय सहायता आसानी से उपलब्ध हो, इस दिशा में:
  - हम झारखण्ड में रियायती दर पर 3 लाख तक का कृषि ऋण प्रदान करेंगे
  - किसानों को बैंकों द्वारा सकल ऋण देयता का 18% कर्ज देने का लक्ष्य है, हमारी सरकार सुदूर क्षेत्रों के किसानों तक इस सुविधा को पहुँचाने का प्रयास करेगी
  - हम सहकारी समितियों के क्षेत्र में दी जाने वाली ऋण राशि को बढाकर 200 करोड़ रुपये करने का वितीय प्रावधान करेंगे
- प्रदेश के प्रत्येक किसानों तक हर कल्याणकारी योजना पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए हम मुख्यमंत्री किसान विकास सप्ताह की शुरुआत करेंगे :
  - मुख्यमंत्री किसान विकास सप्ताह, प्रत्येक छह महीने में, प्रखंड स्तर पर, एक सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। इस दौरान, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि झारखण्ड के हर किसान को केंद्र/राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो।
- हम एकल फसल (मोनोक्रॉपिंग) वाली जोत को बहु फसली बनाने के लिए देशज एवं अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा किसानों को सामर्थ्यवान बनाने की दिशा में निरंतर कार्य करेंगे।
- प्रदेश में रबी फसल का उत्पादन महज 20 प्रतिशत होता है। हमारी सरकार का यह संकल्प है कि हम झारखण्ड को दो-फसली कृषि उत्पादक राज्य बनाकर रबी फसल की उपज में 50 % की वृद्धि करने का लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

किसान कल्याण को प्राथमिकता

- हम प्रदेश में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक किसान विकास टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जिसका उद्देश्य किसानों के समग्र विकास के लिए नीतियों/योजनाओं का कुशल क्रियान्वयन करना होगा।
- हमारी सरकार, वर्ष 2020 तक एक कारगर और कल्याणकारी झारखण्ड कृषि और किसान विकास नीति तैयार कर उसका समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।
- हम किसानों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रखंड स्तर पर हर महीने एक किसान सभा का आयोजन करेंगे। इस सभा की अध्यक्षता संबंधित जिलों के जिलाधिकारी करेंगे।
- हम किसानों को बीमा आधारित फसल सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पूर्ण कृषि बीमा योजना शुरू करेंगे। यह पहल खलिहान से बिक्री तक के काल में किसान की फसल को सुरक्षा प्रदान करेगी।

सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण कृषि

- कृषि के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी मौजूद हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, हम प्रदेश के सभी किसानों को निम्न सहयोग प्रदान कराएंगे:
  - प्रत्येक कृषि भूमि का मृदा परिक्षण कराया जाएगा और किसान को उसके आधार पर फसल लगाने की राय दी जाएगी।

- हम 'मिट्टी के डॉक्टर' योजना का व्यापक विस्तार एवं कालबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे, जिससे यह सेवा प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध हो
- हम प्रदेश के प्रत्येक प्रखंड में एक सूक्ष्म मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (माइक्रो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी) और प्रत्येक ज़िले में एक मृदा उपचार-परीक्षण प्रयोगशाला (सॉइल ट्रीटमेंट-टेस्टिंग लेबोरेटरीज) की स्थापना करेंगे

✱ प्रदेश में प्रत्येक किसान के लिए सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज, समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने की दिशा में, हम एक झारखण्ड बीज निगम की स्थापना करेंगे। साथ ही :

- हम उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बीज ग्राम/बीज उत्पादक समूह बनाएंगे। इससे प्रदेश की बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। साथ ही, राज्य के प्रत्येक जिले में बीज भंडार की स्थापना करेंगे
- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न फसलों के एचवाईवी (HYV) और सूखा प्रतिरोधी बीज, सस्ती दरों पर उपलब्ध हो
- हम परंपरागत बीजों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में काम करने वाले कृषि इकाइयों को बढ़ावा देंगे

✱ अन्नदाता से ऊर्जादाता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, भाजपा सरकार किसानों को अनुदानित दर पर सिंचाई के लिए सौर पंप सेट प्रदान करेगी, ग्रिड-कनेक्टेड या ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी और किसानों द्वारा उपार्जित अधिशेष सौर ऊर्जा (सरप्लस सोलर पॉवर) की बिक्री का प्रबंध करेगी।

बेहतर कृषि : सशक्त बुनियाद

✱ हम सभी मौजूदा सिंगल विंडो सिस्टम को कृषि सहायता केंद्र के रूप में विकसित करेंगे, जिससे हर किसान को कृषि संबंधी सेवाएं उनके द्वार पर ही उपलब्ध हो सके। इन केंद्रों को सुदृढ़ करते हुए निम्न सेवाएँ प्रदान करेंगे :

- इन केंद्रों के माध्यम से हर किसान को समय पर बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि सम्बन्धी मशीनरी इत्यादि सेवाएँ प्रदान करेंगे
- इन केंद्रों में कृषि सम्बंधित भण्डारण, विपणन, निर्यात इत्यादि के सन्दर्भ में सहायता प्रदान करेंगे
- कृषि सहायता केंद्र के माध्यम से रबी और खरीफ फसल के पूर्व, कृषि जागरुकता कार्यशाला का आयोजन कराएंगे, जिससे किसान को कृषि संबंधित प्रौद्योगिकी और तकनीक के संदर्भ में नई जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके

✱ हम कृषि उपज की समयबद्ध खरीद (Procurement) सुनिश्चित करने के लिए, प्रदेश के हर प्रखंड में एक खरीद केंद्र (Procurement Center) की स्थापना करेंगे।

✱ हम प्रदेश में एक अत्याधुनिक एग्रो लॉजिस्टिक नेटवर्क स्थापित करेंगे। इस नेटवर्क के अंतर्गत:

- सभी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज (शीत भंडारघर), वेयरहाउसिंग यूनिट (माल-गोदाम), विपणन केंद्र और डीहूमिफ़ाइड चैंबर्स (शुष्क कक्ष) का एक मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क स्थापित करेंगे
- पूरे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों (फूड प्रोसेसिंग प्लांट) का निर्माण करेंगे
- खाद्यानों और विशेषकर फल एवं सब्जियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए, हर प्रखंडों में एक मिनी कोल्ड स्टोरेज यूनिट का निर्माण करेंगे। इसके संचालन के लिए, हम सरकारी तौर पर, समर्थन के आधार पर, लोन के आधार पर, पार्टनरशिप या को-ऑपरेटिव के आधार पर सहयोग देंगे

"हमारे देश का किसान जन-जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। मैं किसान का आभार पूर्वक नमन करता हूं।"

- श्री नरेन्द्र मोदी

कृषि-उद्योग का विकास

- कृषि उत्पादों के समर्थन, संरक्षण, संवर्धन एवं विपणन के लिए एक सशक्त लिंकेज बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
- हम प्रत्येक प्रखंड स्तर पर अत्याधुनिक मंडियों का निर्माण करेंगे एवं वर्तमान में उपस्थित मंडियों को बुनियादी सुविधाएँ जैसे उचित भंडारण की सुविधा, प्रतीक्षालय, कैंटीन, शौचालय, पार्किंग आदि से सुसज्जित करेंगे।
- हम आवश्यकता अनुसार झारखण्ड के सभी प्रमुख शहरों में किसान बाजार का निर्माण करेंगे।
- हम अपने किसानों की बाजार तक की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए राज्य भर में कृषि-निर्यात केंद्र का निर्माण करेंगे।
- हम कृषि आधारित उद्योग को विकसित करने और कृषि से जुड़े उद्यमियों को हर प्रकार का सहयोग प्रदान करने हेतु झारखण्ड एग्री इन्वेस्टमेंट (JAI) कोष बनाएंगे। हम इस कोष के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों से जुड़े उद्यमियों, स्टार्ट-अप या अन्य ऐसे वर्गों के व्यवसाय को विकसित करने हेतु प्रारंभिक पूंजी और रियायती ऋण प्रदान करेंगे।
- हम पूरे प्रदेश में 500 एफपीओ का गठन करेंगे और उन्हें प्रारंभिक पूंजी और रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

ज्ञान-कौशल पर आधारित कृषि का विस्तार

- हम 5,000 किसानों को कृषि (विशेषकर समृद्ध एवं सतत कृषि) और उससे संबंधित क्षेत्रों में विकसित हो रही नई या उन्नत प्रणाली की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश और देश के अन्य क्षेत्रों में भेजेंगे।
- हम पूरे प्रदेश में आवश्यकता के आधार पर कृषि-अनुसंधान संस्थान, पशु चिकित्सा महाविद्यालय और कृषि-कौशल विकास केंद्र स्थापित करेंगे और प्रदेश के महाविद्यालयों में कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि-अनुसंधान संस्थानों और कृषि-कौशल विकास केंद्रों में पारंपरिक एवं आधुनिक कृषि विधियों को सीखाया जाएगा।
- हमारी सरकार, कृषि विज्ञान केंद्रों एवं बिरसा कृषि विश्विद्यालय में कृषि उत्पादन एवं प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित कर, समर्थन प्रदान करेगी। इस कदम से किसान को आधुनिक-उन्नत तरीकों से कृषि के विभिन्न रूपों से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
- हम प्रत्येक प्रखंड में कृषि कौशल विकास केंद्र और प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण करेंगे।
- हम कृषि विभाग में रिक्त तकनीकी पदों पर कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थानों के सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे

झारखण्ड को बनाएंगे बागवानी का केंद्र

- हम कृषि के अंतर्गत बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने के लिए एक विशेष मिशन शुरू करेंगे। हम लंबी अवधि के लिए पेरिशबल्स आइटम (नष्ट होने वाली सामग्री) को संग्रहित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को समर्थन प्रदान करेंगे और पूरे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) इकाई स्थापित करेंगे।
- हम प्रदेश के सभी प्रखंडों में माइक्रो ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट (सूक्ष्म जल बूंद सिंचाई परियोजना) द्वारा झारखण्ड बागवानी गहनता का विस्तार करेंगे।
- हम झारखण्ड बागवानी उत्पादों का बाजार बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र (फूड प्रोसेसिंग प्लांट) स्थापित करेंगे।
- हम प्रदेश में कृषि वानिकी को विकसित करने के लिए, प्रदेश के सभी प्रखंडों में बिरसा मुंडा बागवानी योजना का विस्तार करेंगे, जिससे जनजातीय समुदाय, छोटे और सीमांत किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण हो सके।
- हम सूखी खेती , बागाती खेती , दलहन, तिलहन को अधिक बढ़ावा देंगे।
- कृषि कार्य के लिए उपलब्ध योग्य भूमि को खेती, बागान, बांस, केला, फल के वृक्ष आदि के उपयोग में लाकर विशेष रूप से आर्थिक लाभ में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे 10 लाख हेक्टेयर भूमि को उपयोगी बनाए जाने का कार्य किया जाएगा।
- हम अनुपयुक्त वन भूमि 'जो पट्टे के अधीन नहीं आई हो'- उस भूमि को वनों के अन्दर रहने वाले जनजातीय समाज के लोगों की वन आधारित आजीविका के लिए विकसित करने का कार्यक्रम शुरु करेंगे।

दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा

- हम दूध के उत्पादन को दोगुना करने और मेधा डेयरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुग्ध धारा मिशन की शुरुआत करेंगे। भाजपा सरकार, गरीब किसान को अनुदानित देसी नस्ल की गाय उपलब्ध करा रही है, जिसे और विस्तारित किया जाएगा।
- हम डेयरी में शामिल स्वयं सहायता समूहों को अनुदान पर मिनी इंसुलेटेड दुग्ध टैंक प्रदान करेंगे। साथ ही, झारखण्ड में दूध खरीदी इकाइयों/कलेक्शन सेंटर का विस्तार करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक इकाई उपलब्ध हो।
- हम प्रदेश में पशुधन को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल वेटनरी क्लीनिक सर्विस (चलंत पशु चिकित्सा क्लिनिक सेवा) शुरू करेंगे।
- हम मनरेगा के अंतर्गत, सामुदायिक चारागाह बनवाने के कार्य को शीध्रता से कार्यान्वित करेंगे और साथ ही ग्राम सभा स्तर पर इन चारागाहों के लिए संधारण की व्यवस्था भी करेंगे।
- हम पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था को और सशक्त बनाएंगे और खुरह एवं खुटहन (खुरपका और मुहपका) आदि रोगों का कालबद्ध उन्मूलन करेंगे।
- प्रदेश में पशुचारा की उपलब्धता एवं सहज उत्पादन के लिए विभिन्न तकनीक का प्रयोग किया जाएगा।
- हम गो-पालक वर्ग से जुड़े नागरिकों के लिए पीपीपी मोड में 'गोष्ठम योजना' के तहत सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेंगे।
- हम अपने प्रदेश में कुक्कुट पालन, सुअर पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन के माध्यम से हो रही आय में गुणात्मक वृद्धि के लिए उन्नत किस्म के पशुओं को अनुदानित दर पर अपेक्षित गरीबों के बीच वितरित करेंगे।

नीली क्रांति की ओर तेज़ कदम

- विगत 5 वर्षों में, झारखण्ड ने मछली उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित किया है। मत्स्य पालन हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भाजपा सरकार ने अहम भूमिका निभाई है, इससे मत्स्य कृषकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2011-12 से 2016-17 तक इस क्षेत्र में लगभग 70000 एमटी से 2.25 लाख एमटी, लगभग 10 प्रतिशत के दर से विकास हुआ है। हम प्रतिबद्ध है कि प्रदेश में केज सिस्टम को और विकसित करेंगे। सवा दो लाख एमटी से अधिक उत्पादन कर नीली क्रांति को और आगे ले जाएंगे।
- हम प्रदेश के प्रत्येक प्रखंड में एक मत्स्य पालन सहायता केंद्र स्थापित करेंगे। ये केंद्र, वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे और मत्स्य पालन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति या एस.एच.जी. को हर तकनीकी, आधारभूत सुविधा और अनुदानित आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।
- हम लघु और सीमांत मत्स्य पालकों को मछली के संरक्षण के लिए अनुदानित दर पर आइस-बॉक्स प्रदान करेंगे।
- हम झारखण्ड में लाभकारी केज फिश फार्मिंग तकनीक का विस्तार करेंगे जिससे कमर्शियल मत्स्य पालन का वृहद् विकास हो।
- हम प्रदेश में मत्स्य पालन के लिए 50 उत्पादक समूह बनाएंगे। इन उत्पादक समूहों को उनके विकास के लिए वित्तीय, तकनीकी और बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करेंगे।
- हम मत्स्य विभाग के अंतर्गत मछुआरा प्रशिक्षक के सभी रिक्त पदों पर एक वर्ष के अंदर नियुक्तियां करेंगे।

जैविक कृषि

- झारखण्ड में जैविक उत्पाद के लिए उपयुक्त परिवेश है। भारत सरकार ने भी जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए तेज पहल की है, हमारी सरकार विशेष पहल कर किसानों को पूर्णत: जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहित करेगी।
- हम 140 जैविक कृषि समूहों का विकास करेंगे और पूरे प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करेंगे (ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स)।

- हमारे प्रदेश में जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए तेज प्रयत्न किए गए हैं। वन एवं वनोपज के आधिक्य तथा पशुपालन के कारण जैविक खाद की उपलब्धता को और सरल बनाने का कार्य करेंगे। हमारा प्रयास यह भी होगा कि कीटनाशक प्रबंधन की उपलब्धता के लिए नीम-महुआ-करंज की खल्ली या अन्य उपलब्ध बीजों से प्राप्त खल्ली का प्रयोग किया जाए।

हर खेत को पानी

- हमारी सरकार जल प्रबंधन से संबंधित सभी विभागों जैसे - लघु सिंचाई सहित जल संसाधन, ग्रामीण विकास, पेयजल और कृषि मंत्रालय के बीच तकनीकी, आर्थिक एवं प्रशासनिक सामंजस्य स्थापित करने हेतु एक जल शक्ति टास्क फोर्स का गठन करेगी।
- भाजपा सरकार सभी खेतों तक विविध प्रकार से आवश्यकता अनुरूप पानी पहुँचाने का कार्य पूर्ण करेगी । हम चेक डैम, श्रृंखलाबद्ध चेक डैम, के साथ साथ आहर, पईन, खांड, नाला, तालाब आदि के माध्यम से छोटी-छोटी जोत तक पानी पहुंचाने का संकल्प करते हैं।
- भाजपा सरकार बड़ी नदियों से यथा कोयल, स्वर्णरेखा, खरकई, दामोदर आदि से संबंधित सभी परियोजना को कालबद्ध तरीके से पूरा करेगी। साथ ही, हम एक राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों का उच्च तकनीकी आयोग बनाएंगे, जिसके माध्यम से प्राप्त सुझावों के आलोक में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- प्रदेश में सूखे और पानी की कमी की समस्या के सम्पूर्ण निवारण हेतु भाजपा सरकार झारखण्ड जल ग्रिड (स्टेट वॉटर ग्रिड) की स्थापना करेगी। प्रस्तावित जल ग्रिड, विभिन्न प्राकृतिक जल निकायों के माध्यम से पानी के बेहतर निकास, वितरण और भंडारण पर लक्षित होगा।
- हम सृजित सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए नए तकनीक का उपयोग करेंगे।
- हम एक वृहद् सर्वेक्षण कराकर प्रदेश में उपलब्ध ऐसे सभी प्राकृतिक संसाधन को चिन्हित करेंगे, जिनमें कम निवेश के साथ छोटी सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित हो सकती हैं। हम सर्वेक्षण आधारित ऐसी छोटी-छोटी योजनाओं को सीमित समय में पूरा करेंगे।
- हम प्रदेश में वृहद् एवं लघु जलाशय (झील) को चिन्हित कर उनके अभिनवीकरण के माध्यम से विशेष सिंचाई क्षमता का सृजन करेंगे।
- हम प्रदेश की सभी छोटी बरसाती नदियों, नालों, पईन, झरनों आदि जल स्रोतों को लघु सिंचाई व्यवस्था के माध्यम से जलाशय बनाकर जोड़ने का संकल्प करते हैं। यह कार्य पंचायत के माध्यम से किया जाएगा । इससे गाँव-गाँव में पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
- हम अगले पांच वर्षों में आवश्यकता अनुसार तालाबों/कुएं का निर्माण करेंगे, जिससे वर्षा जल संचयन और इसका सिंचाई के लिए उपयोग हेतु एक मजबूत प्रणाली का निर्माण हो पाएगा।
- पलामू जिला के अंतर्गत सोन नदी से पानी को लिफ्ट कर विभिन्न जलाशयों में पानी भरने का कार्य किया जायेगा ताकि समय एवं आवश्कयता अनुसार सिंचाई के लिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- हम प्रत्येक किसान को खेती के लिए उपयुक्त मात्रा में बिजली आपूर्ति करेंगे।

जनजातीय विकास का संकल्प

सबको शिक्षा, सबको ज्ञान

- हम वर्ष 2022 तक केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 70 नए एकलव्य मॉडल स्कूलों को तेजी से पूरा करेंगे और प्रदेश में पहाड़िया विद्यालय की संख्या दोगुनी करेंगे।
- हम प्रत्येक जिले में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर जनजातीय लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास स्थापित करेंगे। इन छात्रावासों में पुस्तकालय, मनोरंजन कक्ष, मेस सुविधा, शौचालय, स्नान घर, निरंतर जल और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
- हम झारखण्ड जनजातीय सशक्तिकरण संस्थान की स्थापना करेंगे। यह संस्थान जनजातीय समुदायों की समस्याओं पर अनुसंधान और राज्य में जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए भावी योजना तैयार करेगा।
- हम प्रदेश में राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना में तेजी लाएंगे और अगले 5 वर्षों में इसे पूरा करेंगे।
- हम खूंटी और साहिबगंज में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोजगारोन्मुख शिक्षा हब स्थापित करेंगे।
- हम जनजातीय विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फिनिशिंग स्कूल और मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित करेंगे, साथ ही उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे।
- अनुसूचित जनजाति की युवा शक्ति के प्रशिक्षण कौशल विकास एवं स्वावलम्बन नियोजन के लिए विशेष सेल गठित करेंगे। हर प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण समय पर हो, उपर्युक्त सेल इसका भी मॉनिटरिंग करेगा।
- हम ग्यारहवीं और बारहवीं, स्नातक पाठ्यक्रमों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले जनजातीय विद्यार्थियों के लिए घरेलू और विदेशी एक्सपोज़र ट्रिप, उद्योग एक्सपोज़र ट्रिप की शुरुआत करेंगे।

रोजगार और आजीविका के सुलभ अवसर

- हम झारखण्ड को देश का फॉरेस्ट प्रोड्यूस हब बनाएंगे। इसके लिए कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे:
  - आजीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में एमएफपी/एफपी पर निर्भर समुदायों के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 5 वन उपज इकाइयों की स्थापना करेंगे।
  - प्रदेश में एमएफपी के लिए एमएसपी पर विशेष बोनस प्रदान किया जाएगा।
  - प्रदेश में एमएफपी अनुसंधान के लिए एक नए संस्थान की स्थापना करेंगे जो एमएफपी के उपयोगों को बढ़ाएगा और उससे आजीविका के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- हम रघुनाथ मुर्मू आवासीय कौशल विद्यालय की स्थापना ऐसे स्थानों पर करेंगे, जहां लोगों को भौतिक परेशानियों की वजह से सीखने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। हमारे इस कदम से इन समुदायों के विद्यार्थियों को बाधा मुक्त कौशल शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा और वो आर्थिक रुप से सशक्त हो सकेंगे।
- गुमला, लातेहार और खूंटी में "केन्द्रीय वन शोध संस्थान एवं उद्यमी प्रशिक्षण केन्द्र" खोलने के लिए केन्द्र सरकार से पहल की जाएगी।
- हम कृषि विकास केंद्रों की तर्ज पर वन विकास केंद्र का निर्माण करेंगे।
- हम जनजातीय क्षेत्रों में 25 लाख रुपये तक के टेंडर में जनजातीय संवेदकों को अहर्ता में आवश्यक छूट देकर भागीदारी बढ़ाएंगे जाएगी।
- हम 2024 तक जनजातियों के स्वामित्व वाले स्टार्ट-अप के लिए एक एकीकृत कार्यक्षेत्र और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का वादा करते हैं। हम प्रदेश भर में 48 ऊष्मायन केंद्र और 10 उद्यमशीलता केंद्र स्थापित करेंगे और जनजातीय उद्यमियों के लिए योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन देंगे।
- हम जनजातीय युवाओं के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु स्कूल स्थापित करेंगे, जिससे वे सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों में शामिल हो सकें।
- हम सेना एवं अर्ध-सैनिक बलों के साथ मिलकर प्रदेश में इन विभागों में चयन की प्रक्रिया के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। सेना

में बहाली के ये कैंप जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे।

- हमारी सरकार ने पहाड़िया बटालियन का गठन किया है। भविष्य में ऐसी नियुक्तियों के लिए हमारी सरकार प्रोत्साहन देगी।
- हम सरकारी विभागों में जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरेंगे।
- हम गांवों में फैले देशज हुनर को संसाधन मुहैया कराकर देशज उद्यम के रूप में विकसित कर आर्थिक लाभ की व्यवस्था करेंगे। हमारी सरकार, अगले 3 वर्षों में देशज हुनर को सफल गृह उद्योग में विकसित करने के लिए शोध एवं प्रशिक्षण की सुगम व्यवस्था करेगी।
- हमारी सरकार 'वन-धन विकास' के अन्तर्गत वनौषधि, वनोत्पाद एवं बागानी उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन के माध्यम से रोजगार-स्वरोजगार को बढ़ावा देगी।
- वनवासी बंधुओं की आजीविका प्रोत्साहन के लिए वनभूमि (अपकृष्ट) को मनरेगा एवं ग्रामीण विकास के प्रकल्पों से जोड़कर उपयुक्त खेती-बागवानी का अवसर दिया जाएगा।
- जनजातियों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, हम नई कार्य योजना तैयार करेंगे। इस कार्य योजना का उद्देश्य 2024 तक कार्यबल में जनजातियों की संख्या को 25 लाख तक बढ़ाना है। इस लक्ष्य के प्रति हमारी सरकार निम्न कार्य करेगी:
  - हम जनजातीय क्षेत्र के हर प्रखंड में 'कौशल विकास केंद्र' की स्थापना करेंगे।
  - हम जनजातीय शिल्प/व्यवसाय से संबंधित कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयों, बागवानी, रंगाई, कताई और बुनाई के आधार पर कौशल विकास पाठ्यक्रम विकसित करेंगे।
  - जनजातीय स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए रियायती दरों पर 5,00,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करेंगे।
  - नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक उपकरण और मशीनरी के लिए सब्सिडी प्रदान करेंगे।
  - हम प्रशिक्षित लोगों को प्लेसमेंट के बारे में जानकारी उपलब्ध करने के लिए एक नेटवर्क बनाएंगे।

आदिम जनजातीय समूहों को सामाजिक सुरक्षा

- हमने एक आदिम जनजातीय विकास प्राधिकार गठित किया है जिसे और प्रभावी बनाया जायेगा। यह प्राधिकार इस समुदाय को हर कल्याणकारी योजना का सीधा और कालबद्ध लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य करेगी।
- हमारी सरकार ने आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत दी जानी वाली पेंशन राशि को 600 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये किया है, हम इस कल्याणकारी योजना का विस्तार सुनिश्चित करेंगे।

जनजातीय संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्द्धन

- हम 15 नवंबर, 2024 को भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं वर्षगांठ के लिए उत्सव की शुरुआत करेंगे। हम विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके अद्वितीय योगदान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हम हर वर्ष बिरसा सप्ताह (30 जून से 15 नवंबर के बीच) का आयोजन भी करेंगे।
- हम 3 दिसंबर 2021 को अल्बर्ट एक्का का 50 वां शहीदी दिवस मनाएंगे।
- हम जनजातियों के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण को अपनाएंगे।
- हम जनजातीय संस्कृति के मूल्यों को बनाए रखने को सर्वोच्च महत्त्व देते हैं। हम जनजातीय संस्कृति के पवित्र स्थानों को संरक्षित करने के लिए झारखण्ड जनजातीय संस्कृति संरक्षण कोष का प्रावधान करेंगे।
- हम जनजातीय शोध संस्थान (TRI) के अधीन एक जनजातीय लोक कला और साहित्य प्रकोष्ठ का गठन करेंगे, जो जनजातीय लोक कला में कई त्योहारों और प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। इस प्रकोष्ठ की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होगी:
  - हम हर साल झारखण्ड "जनजातीय साहित्य महोत्सव" का आयोजन करेंगे, जहां जनजातीय इतिहास, मुद्दों और गौरव के बारे में लिखने वाले देश भर के लेखक, कवि जनजातीय संस्कृति और भाषाओं को मानने वाले सभी एक साथ आएंगे।
  - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जनजातीय कला, संगीत और साहित्य को बढ़ावा देंगे।

- जनजातीय वीर गाथा नामक एक डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ बनाकर जनजातियों की उपलब्धियों और इतिहास के बारे में लोगो को बताएँगे।
- जनजातीय कार्यों/साहित्यिक शोध का स्थानीय भाषा से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे।

- हम जनजातीय भाषा और कला पर शोध को बढ़ावा देने के लिए शोधकर्ता को 50,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान देंगे।
- हम जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोलेंगे और इनमें हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ स्थानीय भाषाओं में लिखित पुस्तकें होंगी।
- जनजातीय संस्कृति, विश्व विख्यात है। प्रकृति के साथ समन्वित जीवन पद्धति के विविध रचनात्मक आयाम है। भाजपा इसे समृद्ध, समुन्नत एवं लोकग्राहय करने के लिए विविध आयोजन, कार्यक्रम, प्रतियोगिता आदि का आयोजन करेगी।
- झारखण्ड के अमर शहीदों को श्रद्धा-सुमन स्वरूप उनके पैतृक गांवों को तीन वर्षो के अंदर आदर्श ग्राम बनाएंगे, इस संदर्भ में बजट में प्रावधान किया जाएगा:
  - हमारी सरकार विद्यालय, महाविद्यालय, सरकारी संस्थान, पुरातात्विक स्थल, मेला, संगम आदि का नामकरण शहीदों के नाम पर करेगी
  - राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के जनजातीय महोत्सव आयोजित करेंगे
- बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है। इसे विश्वस्तरीय बनाएंगे और समग्र जनजातीय संस्कृति की झांकी के रूप में राज्य को समर्पित करेंगे।
- विविध कला क्षेत्र के युवक-युवतियों को सरकार उच्च प्रशिक्षण के लिये ख्याति प्राप्त संस्थानों में भेजेगी।

जनजातीय महिलाएं और बच्चे

- हम जनजातीय महिलाओं के पुराने और नए स्वयं सहायता समूहों को 5,00,000 रुपये तक रियायती दर पर ऋण प्रदान करेंगे।
- हम प्रदेश में मानव तस्करी के खतरे को समाप्त करने के लिए समर्पित हैं। हम एक झारखण्ड अभियान के अंतर्गत मानव तस्करों को चिन्हित कर, उनसे सम्बंधित सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करेंगे तथा इस सूचना को पंचायत/गाँव स्तर तक पहुचाएंगे। इस से इनके क्रियाकलाप पर निगरानी रखी जाएगी एवं सरकार को ससमय सूचना मिले जिससे इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।
- हम मानव तस्करी के सम्बन्ध में ग्राम स्तर पर जागरूकता पहुंचाने का कार्य करेंगे।
- हम प्रदेश में कुपोषण के उन्मूलन का वादा करते हैं। वहीं जनजातीय महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे एसएचजी को सामुदायिक पोषण और डे-केयर केंद्र को जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय-प्रबंधित क्रेच, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को भोजन प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हें भविष्य में आजीविका के विकल्प के लिए एसएचजी परामर्श और लिंकेज की व्यवस्था करेंगे। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए गर्म भोजन की व्यवस्था करेंगे।

बुनियादी ढांचे का विकास

- हम प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में जनजातीय विकास समिति को सुदृढ़ करेंगे। हमारी सरकार इन समितियों को 5,00,000 रुपये तक का बजट प्रदान कर रही है। इन समितियों का नेतृत्व जनजातीय समुदायों की एक महिला सदस्य द्वारा किया जा रहा है, जिसे और प्रभावी बनायेंगे।

सशक्त युवा-समृद्ध प्रदेश

रोजगार सृजन का संकल्प

- हम राज्य के हर बीपीएल परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार/स्व-रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- हम निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन देकर स्थानीय युवा आबादी के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे।
- हमने प्रदेश में निवेश और व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए 'मोमेंटम झारखण्ड' की शुरुआत की है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाते रहेंगे की इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों।
- हम प्रदेश भर के हर जिले में अत्याधुनिक बीपीओ परिसरों की स्थापना करेंगे। बीपीओ बिज़नेस को स्थापित करने हेतु स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए रियायती दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएँगे।
- सभी मौजूदा 44 रोजगार एक्सचेंजों को मॉडल करियर केंद्रों में परिवर्तित करेंगे।
- प्रदेश में रिक्त सरकारी पदों पर जल्द ही बहाली करेंगे।
- हम प्रदेश के हर ज़िला/प्रखंड में प्रत्येक वर्ष में तीन बार भर्ती शिविर का आयोजन करेंगे। इस जॉब फेयर से युवाओं को निजी और सार्वजनिक संस्थानों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और नौकरी पाने का अवसर मिलेगा।

उद्यमिता आधारित रोजगार

- स्वरोजगार को बढ़ावा देने और प्रदेश में नए स्टार्ट अप को विकसित करने के लिए 500 करोड़ का झारखण्ड स्टार्टअप प्रमोशन और उद्यमिता कायाकल्प (J-SUPER) फंड की शुरूआत करेंगे।
- प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए तय किए गए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हम एक 'अलग उद्यमिता और नवाचार कोषांग' स्थापित करेंगे। इस सन्दर्भ में, भारतीय उद्यमिता संस्थान, अहमदाबाद की एक शाखा रांची में स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।
- स्टार्टअप्स के लिए एकीकृत कार्यक्षेत्र और लिंकेज आधारित उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए 2024 तक हम पूरे प्रदेश को वर्किंग स्पेस के साथ 48 इन्क्यूबेशन सेंटर और 10 उद्यमी केंद्र स्थापित करेंगे।
- हम प्रदेश में उद्यमशीलता संस्कृति विकसित करने हेतु शैक्षणिक आधार बनाने के लिए उद्यमिता में पाठ्यक्रमों के अनुसंधान और शिक्षण के लिए झारखण्ड राज्य उद्यमिता संस्थान की स्थापना करेंगे। इस तरह के पाठ्यक्रम अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी शुरू किए जाएंगे।
- प्रदेश के उद्यमियों और निवेशकों के ऑनलाइन डेटाबेस के साथ वेब आधारित प्लेटफार्म 'झारखण्ड उद्यमिता विनिमय' बनाएंगे।
- सरकारी विभागों के द्वारा विभाग के काम के लिए प्रासंगिक और नए तकनीकी को अपनाने के लिए एक नीति बनाएंगे।
- महाविद्यालयों, विशेष रूप से विज्ञान और तकनीकी पाठ्यक्रमों में स्टार्ट अप सेल की स्थापना का समर्थन करने के लिए एक योजना की शुरूआत करेंगे, जो विद्यार्थियों को उद्यमिता की जानकारी और जरूरी व्यावसायिक कौशल पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
- राज्य के प्रत्येक शहर और गांव में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए और नए विचारों और उत्पादों को प्राथमिक चरण में फंड देने के लिए 'ग्राम इनोवेशन फंड' की शुरूआत करेंगे। इस फंड का इस्तेमाल विचारों के विकास, प्रोटो टाइपिंग, व्यवहार्यता अध्ययन, आईपीआर सहायता और विकेंद्रीकृत तरीके से बुनियादी उत्पाद परीक्षण करने के लिए किया जाएगा।

लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार सृजन

- हम झारखण्ड में मुद्रा योजना के 100% कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी बैंकों के साथ समन्वय करेंगे।
- स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, वित्तीय सहायता प्रदान करने और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत झारखण्ड को दिए जा रहे बजट को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। जो यह सुनिश्चित करेगा कि झारखण्ड में उद्यमियों को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके।
- हम क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संचालन, विपणन सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन परामर्श और खरीददार सहभागिता प्रदान करने के लिए हर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सुविधा केंद्रों की स्थापना करेंगे।
- पारंपरिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक व्यवसायियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष कोष स्थापित करेंगे।
- एमएसई झारखण्ड के द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं से हम सरकार की वार्षिक खरीद न्यूनतम 30 फीसदी सुनिश्चित करेंगे।

कौशल पूर्ण हर हाथ

- अगले 5 वर्षों में सरकार के विभिन्न कौशल कार्यक्रमों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 20 लाख युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा।
- देश के स्तर पर मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण एवं उद्यमिता सृजन के लिए विशेषज्ञों की सेवा ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के लिए लेंगे।
- हम कौशल युक्त युवाओं के रोजगार एवं स्वरोजगार के तहत नियोजन के लिए सुचारू नेटवर्क बनाने हेतु उद्योग, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग अंतर्गत नियोजन संपर्क सेल स्थापित करेंगे।
- हम हर जिले में दो मेगा कौशल केंद्रों के साथ-साथ प्रदेश में प्रखंड स्तर पर आईटीआई/कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेंगे, ताकि एग्रो-प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, लाइफ साइंसेज, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी आदि जैसे उच्च-केंद्रित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
- प्रदेश के केन्द्रीय लोक उपक्रमों, निजी औधोगिक संस्थानों, उद्योगों के साथ इन नव कौशल युक्त उद्यमियों के प्रशिक्षण की (अप्रेन्टिसशिप) की व्यवस्था करेंगे।
- हम उच्च फोकस क्षेत्रों में मास्टर प्रशिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना करेंगे।
- जिलेवार लक्षित कौशल शिक्षा मॉडल बनाने के लिए हर ज़िले में स्किल की मांग का गहन अध्ययन करके स्किल-डिमांड मैप बनाएंगे। हम विभिन्न क्षेत्रों में काम के अवसरों के लिए मांग के आधार पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यह लक्षित कौशल प्रशिक्षण 100% रोजगार सुनिश्चित करेगा।
- हम प्रदेश भर में विशिष्ट कौशल केंद्रों (उत्कृष्टता केंद्र) की स्थापना करेंगे।

युवा शक्ति प्रोत्साहन

- युवाओं के सामाजिक स्वयंसेवक अवसरों से जोड़ने और उनके व्यक्तिगत विकास में योगदान के लिए एक राज्य स्तरीय वालंटियर कार्यक्रम शुरू करेंगे।
- हम युवाओं के स्व-संगठित समूहों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करेंगे, जो बड़े स्तर पर नागरिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक संपत्ति जैसे स्कूल, अस्पताल, झील, सार्वजनिक उद्यान आदि को अपना कर उनकी स्वच्छता और रखरखाव सुनिश्चित करेंगे।
- शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करने का समर्थन करेंगे, स्थानीय निकायों द्वारा जरूरी कौशल और युवाओं को शहरी एवं ग्रामीण मुद्दों की अधिक जानकारी प्रदान करेंगे।
- हम प्रदेश में कमल क्लब के नेटवर्क का विस्तार करेंगे और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के लिए आवश्यक बजट प्रदान करेंगे।
- हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षा शुल्क में रियायत देंगे।
- 18 से 35 वर्ष के युवाओं को देश के प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्रों और प्रीमियम शैक्षणिक संस्थानों की मुफ्त यात्रा करवाने के लिए हम 'मुख्यमंत्री युवा स्वदेश दर्शन' योजना की शुरुआत करेंगे।

खेल और खिलाड़ी समृद्ध

- हम एक महत्वाकांक्षी योजना 'राज्य क्रीडा प्रतिभा सम्पन्न मिशन' की शुरूआत करेंगे और साथ ही प्रयास करेंगे कि 2024 ओलम्पिक में झारखण्ड के खिलाड़ी अधिक से अधिक मेडल जीते और झारखण्ड को खेल राज्य के रूप में स्थापित करें।
- हम झारखण्ड के सभी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एथलीटों/खिलाड़ियों का अनुदान बढ़ाने के लिए 5 करोड़ का कोष गठित करेंगे।
- हम विभिन्न प्रकार के खेलों, प्रशिक्षकों और खेल प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन को भी शामिल करेंगे।

- हम छोटी उम्र में ही खेल प्रतिभा को विकसित करने हेतु नई क्रीडा प्रोत्साहन नीति लायेंगे जिसके माध्यम से स्कूलों में बच्चों को पारंपरिक शिक्षा के साथ क्रीड़ा भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
- हम खेल में उच्च दक्षता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री खेल छात्रवृत्ति योजना शुरू करेंगे। अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए 25 फीसदी छात्रवृत्ति आरक्षित रहेगी।
- हम वित्तीय सहायता प्रदान कर सभी प्रमुख शहरी केंद्रों में इंटीग्रेटेड स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स की स्थापना करेंगे। इस तरह के परिसरों को पारंपरिक खेलों से संबंधित बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- हम प्रत्येक जिला में उत्कृष्ट स्टेडियम बनाएंगे और प्रखंड स्तर पर खेल के मैदान एवं विद्यालयों मे जिम्नास्टिक प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान करेंगे।
- हम प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में +2 उच्च विद्यालयों के माध्यम से खेल के मैदान, सामग्री, उपकरण एवं प्रशिक्षक की व्यवस्था करेंगे और प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों को +2 उच्च विद्यालयों के साथ कलस्टर में जोड़कर स्पर्धात्मक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे।
- हमारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल प्राप्त करने वाले/वाली खिलाड़ियों को योग्यतानुसार नियोजन की व्यवस्था करेगी।
- हमारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को 60 वर्ष की आयु के उपरांत पेंशन देगी (यदि वे सरकारी सेवा मे न हों)।
- सरकार, प्रदेश में गांव से शहर तक के युवा-युवती की खेल प्रतिभा संवर्द्धन के लिए यथाशीघ्र "खेलनीति" को बहुआयामी बनाएगी।
- हम पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदेश-स्तरीय वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।
- हम झारखण्ड में खेल की संस्कृति के निर्माण के अभिन्न अंग के रूप में फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देंगे और विशेष रूप से स्कूलों और महाविद्यालयों में अभियान की व्यापक जागरूकता और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
- पैरा खेलों में हिस्सा लेने हेतु पैरा-एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए, हम उन्हें 5,000 रुपये का वितीय प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

महिला एवं बाल विकास

बाधा रहित शिक्षा संकल्प

- हम प्रदेश की हर बेटी को बाधा रहित शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से प्रदेश में हर बालिका को के.जी. से पी.जी. तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे।
- हम महिलाओं के लिए साक्षर स्त्री योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें महिलाओं को साक्षर एवं डिजिटल साक्षरता प्रदान करने पर मुख्य रूप से ध्यान रखा जाएगा । यह सरकारी विद्यालयों के शाम की कक्षाओं में संचालित किया जाएगा।
- स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर को शून्य बनाने के लिए 'विद्यालय चले चलाएं अभियान', 'पहले पढ़ाई फिर विदाई' जैसे अभियानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम कार्य योजना को लागू करेंगे।
- हम 'शिक्षा सखी' कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे जिससे प्रदेश में बिना ड्रॉप आउट के 100 फीसदी नामांकन को सुनिश्चित किया जा सके।
- हम प्रदेश के सभी स्कूलों में महिला शौचालयों की व्यवस्था करने के लिए मिशन मोड में काम करेंगे।
- हम पॉलिटेक्निक एवं तकनीकी संस्थानों सहित प्रदेश में मौजूद कॉलेजों की संख्या को दोगुना करेंगे।
- स्कूल स्तर पर गणित और विज्ञान को लेकर छात्राओं की रूचि बढ़ाने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान 'स्टेम एजुकेशन फॉर वुमेन' की शुरूआत करेंगे।

आर्थिक और रोजगार से सशक्तिकरण

- हम प्रदेश में महिलाओं के लिए उपयुक्त सरकारी सेवाओं को चिन्हित कर उन नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण प्रदान करेंगे। इस कदम से महिलाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
- प्रदेश में सखी मंडल (एसएचजी) महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। इन्हें निरंतर समर्थन देने के लिए हम सखी मंडल सशक्तिकरण योजना की शुरूआत करेंगे। जिसके तहत :
  - भाजपा सरकार अगले 5 वर्षों में 1 लाख नए सखी मंडलों का गठन करेगी और 10 लाख से भी अधिक महिलाओं का वित्तीय स्वावलंबन सुनिश्चित करेगी।
  - बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए हम सखी मंडल सदस्यों को आवश्यकता अनुसार मोबाइल फोन प्रदान करेंगे।
  - एसएचजी महिलाओं को रियायती दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- 'महिला उद्योग योजना' के तहत हम एक कोष की स्थापना करेंगे। इस योजना के तहत उन महिलाओं को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं।
- हम 'बैंक मित्र' और 'बैंक सखी' जैसे समुदाय के सुगमकर्ताओं की संख्या को बढ़ाकर सभी परिवारों को 100 फीसदी वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करेंगे, इसके तहत विशेष तौर पर विधवाओं और महिला प्रधान परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- हम किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला सदस्यता वाले एफपीओ को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करेंगे। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि महिला किसानों को ऋण, बाजार लिंकेज और इनपुट तक पहुंच प्राप्त हो।
- हम प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में नए कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना करेंगे।
- आजीविका के अवसरों जैसे सिलाई, खानपान और अन्य सेवाओं जिन्हें घर से किया जा सकता है, ऐसे कार्यों के लिए इन कामकाजी महिला छात्रावासों को प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र में बदलने की दिशा में काम किया जाएगा।
- हम महिला किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने की योजना बनाएंगे और महिला किसानों की पहुंच को ऋण, बाजार लिंकेज और इनपुट तक सुनिश्चित करने के लिए विशेष कोष का प्रावधान करेंगे।
- हम ग्रामीण बीपीओ में महिलाओं के बेहतर रोजगार को सुनिश्चित करेंगे।
- महिलाओं के उत्पादों को बेहतर बाजार प्रदान करने के लिए, हम प्रदेश के हर प्रमुख शहरी केंद्रों में महिलाओं द्वारा संचालित बाजारों की स्थापना करेंगे।

- हम प्रदेश में महिला कौशल केंद्रों की स्थापना करेंगे, साथ ही हम चालित कौशल केन्द्रों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करेंगे।
- महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों का समर्थन करने के लिए 'महिला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग डेवलपमेंट प्रोग्राम' के तहत 24 नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्लस्टर स्थापित करेंगे।

समग्र स्वास्थ्य सेवा

- सुरक्षित मातृत्व के लिए हम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना प्रभावी ढंग से लागू करते हुए सभी सुयोग्य महिलाओं को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता, दो बच्चों तक सुनिश्चित की जाएगी।
- स्तन कैंसर, एनीमिया आदि जैसी बीमारियां जो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, उनकी पहचान के लिए हर साल हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक चिकित्सा शिविर आयोजित करेंगे।
- प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके राज्य में 100 फीसदी संस्थागत प्रसव का प्रयास करेंगे।
- हम अगले वर्षों में राज्य की युवा महिलाओं से एनीमिया के उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेंगे।
- महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम 'सुविधा योजना' का विस्तार करेंगे और सभी सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन उपलब्ध करवाएंगे।
- हम सभी जिला अस्पतालों में मदर चाइल्ड हेल्थ विंग की स्थापना करेंगे और 2025 तक हम आईएमआर को 32 से कम करके 20 और एमएमआर को 208 से 120 करने का प्रयास करेंगे।
- मां एवं बच्चे का पंजीकरण एवं सभी आवश्यक परीक्षाएं, सेवाएं और प्रसवोत्तर देखभाल ठीक तरीके से सुनिश्चित करने के लिए, हम मां और बच्चे की ट्रैकिंग प्रणाली को मजबूत और विस्तारित करेंगे।

बाल कल्याण पर विशेष ध्यान

- अगले पांच वर्षों में झारखण्ड को देश के शीर्ष पांच पोषित राज्यों में शामिल करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए, हम कुपोषण उन्मूलन मिशन की शुरूआत करेंगे। जिसके तहत बच्चों की घर-घर स्क्रीनिंग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और लगातार समर्थन और निगरानी सुनिश्चित करेंगे।
- प्रदेश में कुपोषण उपचार केंद्रों के नवीनीकरण के लिए एक कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे जो प्रत्येक प्रखंड में चिकित्सीय भोजन और दवाओं के साथ मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुधार को सुनिश्चित करेगा।
- हम प्रदेश में पहली बार मातृत्व का सुख भोग रही माताओं को बेबी केयर किट प्रदान करेंगे, जिसमें कंबल, स्लीपिंग पाउच, मॉस्किटो नेट और उन्हें बेबी केयर पर जानकारी के लिए एक बुकलेट होगी।
- हम सिकल सेल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी की शुरूआत करेंगे।
- थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया, पोम्प रोग, गौचर रोग आदि बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए मुफ्त इलाज और दवाई प्रदान करेंगे।
- हम सभी बच्चों और महिलाओं का 100 फीसदी पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करेंगे।

हर नारी सुरक्षित

- प्रदेश के हर जिले में महिला संरक्षण केंद्र की स्थापना करेंगे जिसमें हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे सहायता और संरक्षण प्रदान की जाएगी।
- हम प्रदेश भर में महिला पुलिस स्टेशनों को सुदृढ़ एवं प्रभावी करते हुए महिलाओं के अनुकूल बनाएंगे।
- लिंगानुपात में और सुधार करने एवं लिंगानुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग की एक इकाई बनाएंगे। यह इकाई प्रदेश के प्रगति एवं उम्मीद से कम काम करने वाले जिलों की निगरानी करेगी।
- हम 'शक्तिस्वरूपा' महिला बटालियन का गठन करेंगे और प्रदेश में महिला सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाएंगे।

- तस्करी एवं नक्सल हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास और बाल विकास, समाज कल्याण, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए हम समर्थ योजना की शुरूआत करेंगे।
- हम प्रदेश के सभी जिलों में एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट की स्थापना करेंगे। आधुनिक तकनीकी सहायता सुनिश्चित करेंगे और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे।

अन्य कल्याणकारी नीतियाँ

- भाजपा सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश में गैस चूल्हा और 2 सिलिंडर रिफिल मुफ्त में प्रदान किया है। यह करने वाला झारखण्ड देश में प्रथम राज्य है। हम इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे।
- हम मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत झारखण्ड की बेटियों को 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहे हैं। हम इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए संकल्पित हैं।
- हमारी सरकार ने विधवा और निराश्रित महिलाओं को मिलने वाली प्रति माह पेंशन को 600 से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया है, हम यह सुनिश्चित करेंगे की यह सुविधा सभी विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को मिले ।
- प्रदेश के हर जिले में 5 करोड़ तक की राशि का नारी शक्ति कोष स्थापित करेंगे, जिसका इस्तेमाल महिलाओं से सम्बंधित परियोजनाओं जैसे-उनके कार्य स्थल के पास क्रेच निर्माण, महिला शौचालयों आदि के लिए किया जायेगा।
- हम पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ हर 3 महीने में महिला ग्राम सभा आयोजित करेंगे। जिसमें महिलाओं के मुद्दों का समाधान करने के लिए विचार-विमर्श करेंगे और जेंडर बजट तथा बच्चे से संबंधित सरकारी योजनाओं के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करेंगे। इसके साथ ही, हम प्रदेश भर में प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को नियमित प्रशिक्षित भी करेंगे।
- हम सहिया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाएंगे, जो हमारी सरकार के बनने के 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। समिति की रिपोर्ट में सिफ़ारिशों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
- हम सहिया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे।
- आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे का सुधार करने और सभी आवश्यक स्थानों पर नए केंद्र स्थापित करने के लिए हम बड़े पैमाने पर 200 करोड़ के बजट से आंगनवाड़ी नवीनीकरण मिशन की शुरूआत करेंगे।

"हमारी मातृशक्ति हमारा गर्व है, महिला सशक्तिकरण हमारे विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है"

- श्री नरेन्द्र मोदी

सबका साथ, सबका विकास

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का कल्याण

- हम पं. दीनदयाल उपाध्याय पीडीएस टास्क फोर्स की स्थापना करेंगे जो पीडीएस प्रणाली को सुधारने का काम करेंगी। पीडीएस प्रणाली की कड़ी निगरानी करेंगे और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को पीडीएस की दुकानों से जोड़ेंगे ताकि हर जरुरतमंद के घर तक राशन पहुंच सके। डाकिया प्रणाली की जीपीएस सिस्टम के माध्यम से और मजबूत निगरानी करेंगे।
- हम पीडीएस योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिए दाल भी उपलब्ध कराएँगे।
- 'मुख्यमंत्री कैंटीन योजना' के अंतर्गत लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन को और सुलभ बनाने के लिए प्रदेश में इस योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन करेंगे। लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हम कैंटीन में आरओ सिस्टम लगाएंगे। ये कैंटीन रात में भी खुली रहेगी।
- केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को प्रदेश में बरकरार रखेगा।
- हम 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम जिला स्तर पर ईडब्ल्यूएस कल्याण टास्क फोर्स की स्थापना करेंगे, जो प्रदेश भर के सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों की पहचान करेगा और नागरिकों को प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से राज्य में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की सुविधा प्रदान करेगा।
- हम जल निकासी, सड़कों और समुदायिक शौचालयों में सुधार करके झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे। स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए बस्तियों में जागरूकता शिविर भी लगाएंगे।
- हम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए अन्य आरक्षित वर्गों के लिए चालित छात्रवृति योजना के तर्ज पर एक झारखण्ड स्टेट इ.डब्लू.एस प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत करेंगे। इस छात्रवृत्ति की निम्नलिखित विशेषताएं होंगी-
  - प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2,200 रुपये दिए जायेंगे।
  - पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 7,500 रुपये दिए जायेंगे।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

- अनुसूचित जाति से संबंधित बच्चों की छात्रवृत्ति राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों और महाविद्यालयों को ई-कल्याण पोर्टल से रजिस्टर किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए झारखण्ड स्टेट पोस्ट मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत दी जाने वाली राशि में वांछित वृद्धि करेंगे।
- अनुसूचित जाति के युवाओं में उद्यमशीलता की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड अनुसूचित जाति निगम के तहत एक विशेष कोष की शुरूआत करेंगे। अनुसूचित जाति के युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का रियायती ऋण प्रदान करेंगे।
- झारखण्ड एजुकेशन लोन गारंटी योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- हम हर जिले में स्थापित कौशल प्रशिक्षण और विकास केंद्रों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मुफ्त प्रशिक्षण देंगे।

ओबीसी का कल्याण

- हमारी सरकार ने पिछड़े वर्ग की जनसँख्या के गहन सर्वेक्षण का आदेश दे दिया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के 6 माह के अन्दर हम संविधान के दायरे में उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का कार्य करेंगे।
- ओबीसी बच्चों की छात्रवृत्ति की राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों और महाविद्यालयों को ई-कल्याण पोर्टल से रजिस्टर किया जाएगा।
- हम ओबीसी विद्यार्थियों को 'झारखण्ड राज्य पोस्ट मैट्रिक और प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत प्रति वर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वांछित वृद्धि करेंगे।
- स्व-रोजगार करने के इच्छुक ओबीसी युवाओं के लिए 5 लाख रुपये तक का रियायती दर पर ऋण प्रदान करने के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त निगम की स्थापना की गई है, जिसे सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया जायेगा।

- 'झारखण्ड शिक्षा ऋण गारंटी योजना' के तहत ओबीसी समुदायों के विद्यार्थियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
- प्रदेश के हर जिले में स्थापित कौशल प्रशिक्षण और विकास केंद्रों में हम ओबीसी विद्यार्थियों को भी अनुदानित प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

खनिकों का कल्याण

- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि खदान के ऑपरेटर खदान मजदूरों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। जो निम्नलिखित हैं-
  - खनिको के बच्चों के लिए क्रेच
  - 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा
  - ब्रेक के दौरान खदान कर्मचारियों के लिए बिस्तर के साथ मनोरंजन की सुविधा
  - साइट पर मोबाइल एम्बुलेंस
  - सुरक्षा उपकरण
  - आपातकाल के मामलों में तकनीकी सहायता और निकासी सहायता प्रदान करने के लिए हर समय खनन स्थलों पर प्रशिक्षित पर्यवेक्षक की उपलब्धता
- हम जिला खनिज निधि के तहत प्राप्त धन के प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धन का उपयोग उस जिले में स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण सुधार और जल रि-साइकिल के लिए हो रहा है।
- 50 फीसदी कुशल श्रमिको की मांग को स्थानीय संसाधनों से पूरा करने के लिए हम खदान संचालकों को प्रोत्साहित करेंगे।
- हम अनुबंध मजदूरों को बेहतर रोजगार और कार्यस्थल प्रदान करने हेतु सम्बंधित इकाइयों के साथ कार्य योजना तैयार करेंगे।

फैक्टरी मजदूर

- हम कारख़ानों में कार्यरत कर्मचारियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेंगे जिससे नौकरी करते हुए नए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करें।
- हम कौशल प्रशिक्षण और विकास केंद्रों के तहत प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल श्रम में 10 लाख असंगठित श्रमिकों को जोड़ने का वादा करते हैं।

बुनकर कल्याण

- हम झारखण्ड में हथकरघा और कपड़ा उत्पादन क्लस्टर को बढ़ावा देने हेतु कोल्हान, पलामू और संथाल परगना में एक-एक मेगा परिधान पार्क की स्थापना करेंगे।
- हम राँची में कला व्यापार सुविधा केंद्र और कपड़ा संग्रहालय की स्थापना करेंगे।

अल्पसंख्यकों का कल्याण

- मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए SPQEM योजना को सभी मदरसों में लागू किया जाएगा।
- जैन समुदाय के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पारसनाथ मंदिर और इटखोरी मंदिर को संरक्षित करने के लिए 20 करोड़ रुपये का कोष प्रदान करेंगे।
- आर्थिक रूप से कमज़ोर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण देंगे।
- हम अल्पसंख्यक समाज की समस्याओं का सामाजिक-आर्थिक तौर पर अलग-अलग अध्ययन करने के लिए अल्पसंख्यक अध्ययन समिति का गठन करेंगे।
- 1984 के दंगों से प्रभावित वैसे सिखों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी, जिसको अब तक नहीं दी गयी है।

असंगठित श्रमिक का कल्याण

- हम पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत सभी असंगठित श्रमिकों के नामांकन को पूरा करने के लिए प्रदेश के हर प्रखंड में शिविरों का आयोजन करेंगे।
- हम प्रदेश के हर प्रखंड में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए डे-केयर क्रेच स्थापित करेंगे।
- झारखण्ड के असंगठित मजदूरों की शिकायतों का निवारण करने के लिए हम झारखण्ड के श्रम प्रबंधन पोर्टल 'श्रमाधान' के तहत एक सामाजिक सुरक्षा समिति स्थापित करेंगे।

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

- ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो समाज के विविध क्षेत्र में समाजसेवा का कार्य करना चाहते हों, उनको प्रोत्साहित करने की व्यवस्था करेंगे।
- हमारी सरकार ने वृद्धा पेंशन को 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह किया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सुयोग्य को इसका शत प्रतिशत लाभ मिले।
- हम 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित तीर्थ यात्रा सर्किट की व्यवस्था करेंगे, जो चारधाम यात्रा, देवघर ज्योतिर्लिंग दर्शन और काशी की यात्राएं कराएगी।
- हम सभी वरीय (विशेषकर पेंशनर) व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु नीतिगत रूप से उन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने की दिशा में कार्य करेंगे।

दिव्यांगों का कल्याण

- हमारी सरकार ने दिव्यांग पेंशन को 600 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह किया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सुयोग्य को इसका शत प्रतिशत लाभ मिले।
- हम सभी सार्वजनिक भवनों और सार्वजनिक परिवहन को दिव्यांगों के अनुकूल बनाएंगे जिससे सुगम्य भारत अभियान सुनिश्चित किया जा सके।
- हम प्रदेश के प्रत्येक जिले में दिव्यांगों के लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना करेंगे ताकि हम उनके लिए कार्यबल में प्रवेश करने का अवसर प्रदान कर सके।
- हमारी सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में चल रही प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि में वांछित वृद्धि करेगी।
- हम सुनिश्चित करेंगे कि झारखण्ड में दिव्यांगों को केंद्र सरकार द्वारा उपकरण खरीद / फिटिंग के लिए दी जाने वाली सहायता योजना (एडिप) के तहत सभी लाभ प्राप्त हो।
- हम सभी सरकारी विभागों में दिव्यांगों के लिए दिए गए आरक्षण को सशक्त रूप से लागू करेंगे।
- हम प्रदेश के स्कूलों में दिव्यांग शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित करेंगे।

सरकारी कर्मचारियों का कल्याण

- सरकारी नौकरी में रिक्त पदों पर बहाली के लिए हम एक विशेष अभियान चलाएंगे।
- हम सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में क्रेच का निर्माण करेंगे।
- हम सभी सरकारी कार्यालयों को कंप्यूटर, प्रिंटर, एसी, 24*7 बिजली, वाईफाई, पीने के पानी सहित नवीनतम सुविधाओं से लैस करेंगे।
- ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता के साथ, क्रेच, सुपरमार्ट्स, सामुदायिक केंद्र और 24*7 बिजली आपूर्ति के साथ एकीकृत आवास परिसरों का निर्माण करने का वादा करते हैं।

पूर्व सैनिकों/पेंशनर कल्याण

- पूर्व सैनिक के कोटे के सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों को बैकलॉग कर आगे बढ़ाया जाएगा और उम्मीदवारों की उपलब्धता को मंजूरी दी जाएगी।
- हम विभिन्न सेवाओं से सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मचारी को उनकी रूचि के अनुसार सामाजिक कार्य करने के अवसरों का सृजन करेंगे।

वकीलों का कल्याण

- हमारी सरकार सभी अधिवक्ताओं को आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने हेतु विशेष कार्य योजना बनाएगी।
- प्रदेश के सभी न्यायलय परिसरों में वकीलों के बैठने की व्यवस्था को बेहतर एवं सुगम किया जायेगा।

ऑटो ड्राइवर्स/लॉरी ड्राइवर्स /ई-रिक्शा/टैक्सी ड्राइवर्स का कल्याण

- हम डीजल/पेट्रोल से चलने वाले सभी ऑटो रिक्शा को सीएनजी में बदलने के लिए अगले पांच वर्षो में रूपांतरण योजना शुरू करेंगे।
- हम प्रदेश भर में ट्रक/बस ड्राइवरों के लिए विश्राम हेतु मार्गीय सुविधा को विकसित करेंगे।
- हम सुनिश्चित करेंगे की सभी माल एवं सवारी परिवहन कर्मियों (रेल छोड़ कर) को केंद्र सरकार की योजना जैसे कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत और अटल पेंशन योजना में लाभान्वित करने हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे।

सफ़ाई कर्मचारी

- हम रात में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएँगे।
- हम प्रदेश की स्वच्छता को बनाए रखने की प्रक्रिया प्रभावी बनाते हुए, सफाई कर्मचारियों को एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने की दिशा में आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेंगे।

पत्रकार कल्याण

- हमारी सरकार ने पत्रकारों के लिए 7,500 रुपये की पेंशन और फैमिली पेंशन देने की व्यवस्था, झारखण्ड में पहली बार की है। हम इस योजना को प्रभावी रूप से लागु करेंगे।
- पत्रकारिता से जुड़े (इलेक्ट्रॉनिक, फोटोग्राफर, रिपोर्टर आदि) देहात और छोटे शहरों के तमाम ऐसे बंधु हैं, जिन्हें प्राप्त आय से जीवन-यापन में कठिनाई होती है, हमारी सरकार इस क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्श आधारित कदम उठाएगी।
- आयुष्मान योजना के अंतर्गत अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करने हेतु विशेष कार्य योजना तैयार करेंगे।
- सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभान्वित किया गया है, जिसे प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।

"सबका साथ सबका विकास
सिर्फ नारा नहीं,
बल्कि सुशासन की आत्मा है"

- श्री नरेन्द्र मोदी

अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास

राजकोषीय प्रशासन और आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार

- झारखण्ड सरकार की लगभग सभी सरकारी ज़रूरतों के लिए हम गवर्नमेंट इ-मार्केटप्लेस (GeM) की प्रक्रिया को पूरी निष्ठा से अपनाएंगे।
- हम आर्थिक सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरा करने और राजकोषीय उत्तरदायित्व के मार्ग पर राज्य को आगे बनाने हेतु Center for Fiscal Studies को सुदृढ़ करते हुए उसमें विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे।
- हम राज्य में ढांचागत निवेश के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन करेंगे।
- हम भारत सरकार के साथ मिल कर HEC का नियंत्रण परमाणु ऊर्जा विभाग को सौपने की दिशा में कार्य करेंगे।
- हम स्टील रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ़ इंडिया के मुख्यालय को रांची में स्थापित करने की दिशा में कदम उठाएंगे।
- हमारी सरकार निजी औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करेगी जिससे विनिर्माण के साथ-साथ सर्विस सेक्टर भी विकसित हो सके।
- हम उद्योगों को प्रोत्साहक अनुदान एवं अन्य सहायता देने की प्रक्रिया का कालबद्ध रूप से क्रियान्वयन करेंगे।
- हम सरकारी उपक्रमों के लिए नीति निर्धारण में प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों को शामिल करेंगे, जिससे नीति निर्माण को और सशक्त बनाया जा सके।
- हम ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस और मोमेंटम झारखण्ड के आलोक में औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास के लिए बंद पड़े उद्योगों को पुनः स्थापन करने की दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे।
- हम सशक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए प्रदेश में निवेश को बढ़ाने की दिशा में कार्यरत रहेंगे। साथ ही संसाधन अभिवृद्धि के लिए ठोस कदम उठाएंगे।
- हमारी सरकार, प्रदेश में देसज, खादी और ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु बनाई गयी योजनाओं का कियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

एक अनुकूल व्यावसायिक वातावरण का संकल्प

- निरीक्षणों को सीमित करते हुए हम कानून अनुपालन की व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा स्व-सत्यापन आधारित करने के लिए कदम उठाएंगे।
- राष्ट्रीय मानकों को अपना कर ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (मैन्युफैक्चरिंग) में झारखण्ड को देश में अव्वल प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस के लिए हम फैक्टरियों की बिल्डिंग प्लानों का ऑनलाइन अप्रूवल, निरीक्षकों का तेज़ी से आवंटन और निरीक्षण चेकलिस्टों और प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने पर ध्यान देंगे।
- हम व्यापार के क्षेत्र में डिजिटलीकरण के साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ये सभी सेवाएँ ऑफलाइन भी समयबद्ध रूप से प्राप्त हो सकें।
- मुख्यमंत्री के अधीन एक विशेष टास्क फ़ोर्स बनाएंगे जो औद्योगिक योजनाओं का कार्यान्वन सुनिश्चित करेगा और 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की औद्योगिक परियोजनाओं से प्रशासनिक अड़चनों का निवारण किया जाएगा। इसी टास्क फ़ोर्स को झारखण्ड मोमेंटम प्रोग्राम की प्रगति पर ध्यान देने की जिम्मेदारी भी देंगे।
- हम रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नियामक कदमों का विस्तार करेंगे।
- हमारी सरकार स्टार्ट-अप के लिए मेंटर की सेवा प्रदान करने के लिए एक प्लेटफार्म का गठन करेगी।

औद्योगिक आधारभूत संरचना को बढ़ाने का संकल्प

- हम 2024 तक झारखण्ड को पूर्वी भारत का लॉजिस्टिक हब बनाएंगे। इस उद्देश्य से:
  - ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) के पास झारखण्ड में एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) का निर्माण होगा।

- हम साहिबगंज इंटीग्रेटेड फ्रेट टर्मिनस में और निवेश करेंगे और राज्य के अन्य औद्योगिक समूहों से इस टर्मिनस तक कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे।

- भारतमाला योजना के अंतर्गत विचाराधीन साहिबगंज से बहरागोडा तक की सड़क निर्माण परियोजना के अंतर्गत, हम सड़क के दोनों ओर की भूमि को एक डेवलपमेंट कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे।

- रांची-गोला-धनबाद-बोकारो होते हुए दुमका तक स्वीकृत एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लोक हित में तीन वर्षों के अन्दर पूरा करेंगे

- हम अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास निजी औद्योगिक एस्टेट क्लस्टर बनाएंगे, जो विनिर्माण के लिए विशेष प्रोत्साहन के माध्यम से प्रदेश में विनिर्माण को बढ़ावा देगा।

- प्रदेश में सभी नए और वर्तमान उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने हेतु, हमारी सरकार हितधारकों को न्यूनतम सुविधा पैकेज प्रदान करेगी। इस कदम के तहत, भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाएँ जैसे बिजली-पानी की आपूर्ति, डिजिटल कनेक्टिविटी, सड़कों आदि की कालबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

झारखंड में रोज़गार और बेहतर जीवन को बढ़ावा

- अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास बनी सरकारी और निजी उद्योग क्लस्टरों को ऑपरच्युनिटी क्लस्टरों का दर्जा देंगे।

- हम अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर/ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास बने क्लस्टर और औद्योगिक एस्टेट के कर्मचारियों के लिए रहने योग्य और आकर्षक बनाने के लिए FAR मानदंडों में छूट और मिक्स्ड जोनिंग की अनुमति देंगे।

- टेक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को फोकस सेक्टर बनाएंगे और AKIC/EDFC के पास विभिन्न टेक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण पार्क बनाएंगे।

- केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य के माइनिंग सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि माइनिंग सेक्टर में नौकरियों का सृजन बढ़ सके। इसी उद्देश्य से नियमों के उल्लंघन की वजह से बंद हुई खदानों को उचित पहल लेकर फिर से खोलने का प्रयास करेंगे।

- प्रदेश का पलामू प्रमंडल अक्सर सूखे से प्रभावित रहता है, इसका परिणाम अकाल, भूखमरी, पलायन और बेरोजगारी होती है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम पलामू प्रमंडल में वृहद्, लघु खनिज सम्पदा आधारित उद्योग स्थापित करेंगे एवं इस क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार निवेश के लिए प्रयत्न करेंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का विकास

- हम झारखण्ड आधारित सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और एसएमई उद्योगों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से जुड़ने की सुविधा देंगे।

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के उद्योगों में रोजगार सृजन और इन उद्योगों के विस्तार हेतु प्रचलित योजनाओं और नीतियों की पहचान और क्रियान्वयन के लिए हम एक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग टास्क फ़ोर्स का गठन करेंगे। इस टास्क फ़ोर्स में इस क्षेत्र के मशहूर उद्यमियों को सम्मिलित किया जाएगा।

- हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग तथा एसएमई उद्योगों को उपलब्ध विनियामक और वित्तीय प्रोत्साहनों को उनके बड़े उद्योगों के रूप में विकसित हो जाने के 5 साल बाद तक जारी रखेंगे।

- टैक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के केंद्रित क्षेत्रों में हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को उपलब्ध विनियामक और वित्तीय प्रोत्साहनों को उनके बड़े उद्योगों के रूप में विकसित हो जाने के 7 साल बाद तक जारी रखेंगे।

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, एसएमई और छोटे व्यापारियों को जीएसटी अनुपालन, कानूनी अनुपालन और ऑडिट अनुपालन हेतु सब्सिडी देने के लिए 'झारखण्ड व्यापार एवं लघु उद्योग सुगम योजना' शुरू करेंगे।

- जमशेदपुर में एक 'मेकर्स स्पेस' की स्थापना करेंगे जो विनिर्माण के स्टार्ट अप को आधुनिक मशीनों की सुविधा प्रधान करेगा और इन स्टार्ट अप के विकास में मदद करेगा।

- हम झारखण्ड के सभी प्रखंड मुख्यालयों में स्थानीय विक्रेता और कारीगर संस्थाओं की साझेदारी में, स्थानीय रियल एस्टेट डेवलपर्स के माध्यम से अत्याधुनिक रीटेल बाज़ारों का निर्माण करेंगे।

झारखण्ड में विकास की नींव

सड़कों का विकास

- हम सुनिश्चित करेंगे कि अगले पांच वर्षो में झारखण्ड के प्रत्येक बासगीत तक गुणवत्ता पूर्ण कनेक्टिविटी उपलब्ध हो :
  - 2024 तक झारखण्ड में 6000 कि.मी. नयी राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा । साथ ही 16,000 कि.मी. अन्य नयी सड़कों का विकास किया जाएगा एवं 15 शहरों में बाइपास का निर्माण किया जाएगा।
  - हम प्रदेश में अन्तर-जिला सड़कमार्ग, जिलान्तर्गत सड़कमार्ग एवं अंतरराज्यीय सड़क मार्गों का विकास करेंगे ।
  - 150 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण करेंगे एवं राँची में पूर्व प्रस्तावित इनर रिंग रोड का निर्माण तीन वर्ष के अंदर कराया जाएगा।
- प्रदेश के अंतिम छोर को जोड़ने के लिए 8 लेन झारखण्ड माला राजमार्ग का निर्माण करवाएंगे ताकि सुनिश्चित हो सके कि प्रदेश के सभी जिले एक दूसरे से जुड़े हो।
- झारखण्ड में राष्ट्रीय राजमार्गो का एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए हम प्रदेश में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को कालबद्ध रूप से पूरा करने की दिशा में कार्य करेंगे।
- झारखण्ड में सड़कों के नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए हम मुख्यमंत्री रोड कायाकल्प (रेज्यूवेनेशन) मिशन शुरू करेंगे। 5000 करोड़ निधि के इस मिशन को शुरू किया जाएगा:
  - प्रदेश के दो लेन हाईवे को चार लेन हाईवे में बदलना
  - जिला मुख्यालय से जुड़ी सभी प्रमुख सड़कों को चार लेन वाला राजमार्ग बनाना
  - सिंगल लेन को डबल लेन में एमडीआर या सुधार करना
  - शौचालय, गैस स्टेशन, सुविधा स्टेशन का निर्माण करेंगे और हर 50 किमी पर प्रदेश के सभी राजमार्गो पर 24*7 चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना
- सभी मौसम के लिए प्रदेश के हर गांव और बस्ती में सड़क सुनिश्चित करने के लिए हम एक मिशन की शुरूआत करेंगे। इस मिशन के तहत :
  - हम ग्रामीण सड़कों को पास की प्रमुख सड़कों के साथ जोड़ेंगे
  - मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सभी सड़कों के नियमित रखरखाव के लिए राशि का प्रावधान किया जायेगा
- गुणवत्तापूर्ण काम को समय से पूरा करने, उसकी जवाबदेही को तय करने और सभी अनुबंधों में खराब संचालन और संरक्षण के लिए ठेकेदारों को दंडित करने के लिए हम वित्तीय दंड और ब्लैकलिस्टिंग समेत भारी जुर्माने का प्रावधान करेंगे।

रेलवे

- हमारी सरकार रेल राजस्व अधिप्राप्ति के आलोक में राज्य में नियोजन एवं ढांचागत विकास के लिये रेल मंत्रालय से ठोस प्रयास करेगी ।
- हम रेल मंत्रालय के साथ मिलकर लंबित या चल रही रेल परियोजनाओं के काम को समय पर पूरा करने, नई लाइनें बिछाने, नई ट्रेनें शुरू करने, ट्रैक दोहरीकरण पूरा करने और प्रदेश भर में एक मजबूत रेल नेटवर्क बनाने के लिए विद्युतीकरण का काम करेंगे।
- हम प्रदेश भर में रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और तकनीकी उन्नयन के काम को समय से पूरा करेंगे।
- झारखण्ड और उसके आस पास के महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी और क्षमता को बढ़ाने के लिए रेल के बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने के लिए झारखण्ड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड का गठन करेंगे।
- खनन के पास स्थित रेलवे लाइनों का मूल्यांकन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट और लोगों की मांग के आधार पर इन रेलवे लाइनों को पूरे प्रदेश में पसेंजर ट्रेनों के लिए विकसित करने के लिए हम रेल मंत्रालय के साथ काम करेंगे, इससे पूरे प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

नागर विमानन

- प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को विकसित करने के लिए हम नए हवाई अड्डे स्थापित और विकसित करेंगे।
- प्रदेश में अधिक प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रांची में एविएशन अकादमी स्थापित करेंगे।

भूतल परिवहन

- झारखण्ड सड़क परिवहन विभाग के तहत हम अंतरराज्यीय बस नेटवर्क स्थापित करेंगे। प्रदेश में यह भूतल सेवा को बढ़ाएगा।
- हम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करेंगे और प्रदेश के अंतिम छोर तक सेवाओं को सुनिश्चित करेंगे। हम सुदूर क्षेत्रों में एकीकृत नियोजन, समन्वय और परिवहन सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेंगे।
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने और सेवाओं के अंतिम मील संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए, हम झारखण्ड रिमोट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना करेंगे, जो दूरस्थ क्षेत्रों में एकीकृत नियोजन, समन्वय और परिवहन सेवाओं के लिए एक समर्पित इकाई होगी। हम गुणवत्ता, सस्ती और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सेवा के अंतिम छोर तक उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए मिनीबस नेटवर्क भी तैनात करेंगे।
- हम प्रदेश के पांचों प्रमंडल में मल्टी-मॉडल बस टर्मिनल का निर्माण करेंगे एवं प्रदेश के मुख्य नगरों में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण करेंगे।
- हम अंतर्राज्यीय बस सेवा के लिए राज्य के उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे और उनको समयबद्ध रूप से लाइसेंस और परमिट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

हर घर बिजली की सुविधा

- हम पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को समय पर पूरा करेंगे, जिससे झारखण्ड में बिजली की मांग पूरी होगी। इस परियोजना के पूरा होने से झारखण्ड न सिर्फ बिजली उत्पादन में स्वावलंबी बनेगा, बल्कि अन्य राज्यों को भी बिजली आपूर्ति कर सकेंगे।
- हम प्रदेश के 9 जिलों खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, चतरा, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, लोहरदगा और लातेहार में ट्रांसफार्मर मरम्मत कार्यशाला और केंद्रीय बिजली भंडारण प्रणाली स्थापित करेंगे।
- 'अटल ग्राम ज्योति योजना' के दायरे का विस्तार करने के लिए हम पर्याप्त धन राशि आवंटित करेंगे ताकि प्रत्येक एपीएल/ बीपीएल घर में विद्युतीकरण की सुविधा हो सके।
- प्रदेश ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% विद्युतीकरण प्राप्त किया है। हम प्रदेश के हर घर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
- प्रदेश भर में घरेलू मीटरों के लिए मीटर स्थापना शुल्क को माफ कर दिया जायेगा।
- हम पूरे प्रदेश में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करेंगे और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं में अधिक सब्सिडी देंगे। सभी आवासीय सोसाइटियों को छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हम सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ईडब्ल्यूएस परिवारों को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
- हम जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि के लिए जैव ईंधन नीति का लाभ उठाएंगे और सर्वोत्तम परिणामों के लिए गोबरधन जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करेंगे।
- हम सभी सरकारी भवनों/कार्यालयों/परियोजनाओं के लिए नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग उनकी बिजली की नियमित खपत के एक निश्चित हिस्से के रूप में करना अनिवार्य कर देंगे।

हर घर पेयजल की सुविधा

- हमारी सरकार पाईप लाइन से बचे हुए हर घर को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
- झारखण्ड के गांव में जल निकासी के लिए चल रहे अभियान के आधार पर पंचायत स्तर पर जल का संरक्षण करने के लिए एक जल संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा :
  - इस समिति के सदस्यों को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल के ट्रीटमेंट की विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा
  - ग्रामीण स्तर पर पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और ग्राम स्तर पर सामुदायिक प्रबंधित जल उपचार संयंत्र चलाने के लिए इन समूहों को निजी उद्यमों के साथ जोड़ा जाएगा
  - अगले पांच वर्षों में 5000 सामुदायिक (प्रबंधित) जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे
- भाजपा सरकार जल संरक्षण और पीने योग्य पानी की 24*7 उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले पंचायतों को 10 लाख तक नकद पुरस्कार/प्रोत्साहन देगी।

स्वच्छ झारखण्ड का संकल्प

- हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक झारखण्डवासी की सचेष्ठता से झारखण्ड को 'स्वच्छ झारखण्ड-सुखी झारखण्ड' बनाने का संकल्प सतत् जारी रहेगा।
- स्वच्छता आरोग्य का आधार है। हमारा संकल्प है कि 2024 तक झारखण्ड को देश के शीर्ष राज्यों की तुलना में स्वच्छता में आगे लाएं।
- हम राज्य में 100% कचरा पृथक्करण, संग्रह और प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।
- राज्य में हर नगर निकाय में पक्का सीवरेज और जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।
- नदियों या अन्य जल निकायों में बहने वाली नालियों/सहायक नदियों के लिए सीवेज उपचार सयंत्र बनाया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम उन पंचायतों और शहरों के लिए एक स्पष्ट और ठोस व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान की शुरूआत करेंगे जिनकी (ओडीएफ) खुले में शौच मुक्त के दिशा में धीमी प्रगति रही हैं। हम स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ODF+ और ODF++ प्रोटोकॉल को बड़े पैमाने पर अपनाएंगे।
- हम नीतिगत रूप से उन निजी इकाइयों को जो झारखण्ड में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना चाहती है, को प्रोत्साहित करेंगे । इन इकाइयों में एक पार्टी कचरे से ऊर्जा का उत्पादन करेगी, जबकि अन्य पार्टियाँ नगर निकाय और बिजली वितरण कंपनी होगी, जिससे अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का कार्य सुचारू रूप से चलेगा।

डिजिटल झारखण्ड

- हम दूरदराज / ग्रामीण क्षेत्रों में संचार प्रणाली को उन्नत और मजबूत करके राज्य भर में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे।
- भारतनेट और झारनेट की मदद से हम एक पेपरलेस, कैशलेस झारखण्ड के लिए एक विशेष कार्य योजना बनायेंगे।
- हम प्रदेश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनायेंगे।

सुखी गाँव - समृद्ध गाँव

- हम टोला, गाँव, पंचायत, प्रखंड अर्थात हर स्तर की अलग अलग योजनाओं को कालबद्ध पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं।
- गाँव के विकास के लिए कृषि बागवानी, पशुपालन, वनोत्पाद, हेंडीक्राफ्ट, टूरिज्म के साथ-साथ सम्बंधित सभी विभागों में अभिसरण सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था करेंगे।
- ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य 'ग्रामीण समृद्धि और बेहतर जीवन है ' इसलिए हमारी पार्टी का संकल्प है कि हम जीविका के भिन्न-भिन्न प्रकल्पों को वहां के ग्राम वासियों की सोच प्रवृत्ति पर उपलब्ध संसाधन बाज़ार के आधार पर विकसित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर प्रयास करेंगे।
- प्रायः यह शिकायत आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुँच अपेक्षाकृत कम रहती है, हम वांछित नयी बैंक शाखाएं खोलने के लिए कृत संकल्पित हैं।

- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रज्ञा केंद्र हो और वह जन सेवा केंद्र से जुड़ा हो। हम प्रदेश में प्रत्येक पंचायत में प्रौद्योगिकी और मनोरंजक गतिविधियों से सुसज्जित एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण करेंगे।
- नए सूक्ष्म उद्यम और पुराने ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान करेंगे
- हम 1000 गांवों को शामिल करके आदर्श ग्राम योजना का विस्तार करेंगे।
- प्रदेश में हर गांव और बस्ती को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- सबका सपना-घर हो अपनाः- हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के तहत अबतक 4.68 लाख से अधिक आवास उपलब्ध कराया है। हमारा संकल्प है कि 2022 तक सभी गरीबों को अपना घर का सौगात दे देगें।
- बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत अबतक स्वीकृत 28 हजार आवासों को 2020 तक पूरा कर लाभुक को सौंप देंगे।
- हमारी सरकार 2020 तक राज्य के प्रत्येक गाँव में पेभर ब्लॉक से सड़क का निर्माण करना सुनिश्चित करेगी।
- हम 2020 तक राज्य के सभी गाँव में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

समृद्ध हर शहर

- स्वच्छ भारत मिशन को और सफल बनाने के लिए स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट संसाधन प्रबंधन हेतु विशेष प्रयास करेंगे।
- नगरपालिका के अपशिष्ट जल को कृषि के लिए इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
- हम ULB द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क की संग्रह दक्षता में सुधार के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेंगे।
- हम विकसित हो रहे शहरों के आसपास के परिधीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग के लिए मॉडल दिशानिर्देश विकसित करेंगे और इन दिशा निर्देशों के साथ शहरी विकास योजनाओं को रेखांकित करेंगे।
- प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों को शहर गैस वितरण से जोड़ा जाएगा जो लोगों को पाइप प्राकृतिक गैस (PNG) प्रदान करेगा।
- हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जो सभी ULB के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना तैयार करेगी। उन ULBs को पुरस्कृत किया जायेगा जो विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न टूल का नवाचार करेंगे।
- हम प्रदेश भर के हर शहर में मनोरंजन केंद्रों, पार्कों आदि का निर्माण करेंगे।
- हम प्रदेश में उच्च शिक्षा के संस्थानों में अवसंरचनात्मक विकास पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में काम करेंगे।
- हम देश के प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञ की सहायता से राज्य शहरी विकास प्राधिकार को सुदृढ़ करेंगे । इसका कार्य प्रदेश के सभी मुख्य शहरों के सर्वांगीण विकास की रूप रेखा तैयार करना होगा। हमारी सरकार इस प्राधिकार द्वारा प्रदेश के शहरों की योजनात्मक विकास की दिशा में कार्य करेगी।
- झरिया, जो कभी संयुक्त बिहार की आर्थिक राजधानी मानी जाती थी, आज भूगर्भीय आग के कारण चरम तापन का दंश झेल रही है। हमारी सरकार पूर्व में भी इस पर सचेष्ट रही है तथा आगे राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेगी।

सुशासित प्रदेश, सुरक्षित प्रदेश

सुरक्षित झारखण्ड का संकल्प

- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि झारखण्ड में एक उत्तरदायी, पारदर्शिता-पूर्ण, न्यायसंगत और जन भागीदारी को हर कदम में दर्शाती हुई सुशासन प्रणाली, जिसकी नींव भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में रखी है, उसे अगले पांच वर्षों में और सशक्त बनाई जाए।
- हम एक राज्य कानून और प्रशासनिक सुधार कार्य बल का गठन करेंगे और इस बल के द्वारा अप्रचलित कानूनों में संशोधन कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा, साथ ही अपेक्षित प्रशासनिक संशोधनों को अपनाकर उनका कालबद्ध क्रियान्वयन भी किया जाएगा।
- राज्य में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश सहित अन्य क्षेत्रों से घुसपैठियों का प्रवेश हुआ है, पूर्वी क्षेत्र के कई ज़िले इस से बुरी तरह प्रभावित हैं। इसलिये हमारी सरकार, प्रदेश में एन.आर.सी. लागू करेगी।
- सभी प्रमुख शहरों के संवेदनशील क्षेत्र, सीमाओं के चेक प्वाइंट, राज्य / राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों को सीसीटीवी कैमरों और उचित स्ट्रीट लाइटिंग से कवर किया जाएगा, इससे पुलिस विभाग द्वारा बेहतर निगरानी होगी।
- हम खनन क्षेत्र से संबंधित अपराधों के लिए एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली बनाने की दिशा में काम करेंगे। हम इस उद्देश्य के लिए भारतीय खनन ब्यूरो (आईबीएम) और आईआईटी जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों का सहयोग लेंगे।

पारदर्शी शासन का संकल्प

- चौदह वर्षों तक झारखण्ड नामधारी पार्टियों ने लोक हित में अधिसूचित या गैर अधिसूचित स्थानीय नीति नहीं बनाई जिसके चलते बेरोजगार युवा-युवतियों को नौकरी सहित कई मामलों में असुविधा हुई। हमारी सरकार ने पहली बार झारखण्ड के लिए स्थानीय नीति गठित की है, जिसके तहत सम्बंधित जिले के निवासियों को अगले 10 वर्षों तक वर्ग 3 और 4 की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्तियां की जाएगी।
- सार्वजनिक सेवाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन और कल्याणकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए हम विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु एक संस्थागत व्यवस्था लागू करेंगे, जिससे हर कार्य को लेकर विभाग-वार जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
- हम मिशन मोड में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, उत्तरदायित्व निर्धारित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएंगे और इस व्यवस्था को जनता के समक्ष समयबद्ध रूप से रखा जाएगा।
- प्रदेश में 'एक झारखण्ड' नामक एक डिजिटल प्लेटफार्म का निर्माण करेंगे, जहां सभी नागरिक सेवाओं से संबंधित कार्य किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा जन सेवाएँ उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही, सभी प्रमाण-पत्रों को आवश्यक सेवा प्रदायी अधिनियम के अधीन लाकर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
- हम प्रदेश में भू-अभिलेख के डिजिटलीकरण में हुए त्रुटि का मिशन मोड में 6 माह के अन्दर समाधान करेंगे।
- हम भूमि खरीद-बिक्री के जियो-टैग और लोकेशन एग्नोस्टिक ऑनलाइन पंजीकरण सहित भू-अभिलेखों के व्यापक डिजिटलीकरण का काम करेंगे ताकि प्रदेश, देश को स्पष्ट, अद्यतन और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के साथ-साथ दीर्घकालिक विवादों को कम करने में मदद सुनिश्चित कर सके।
- हम सभी नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवा/प्रमाणपत्र सुविधा प्रदान करने के लिए एक एकीकृत तकनीकी मंच (यूनिफाइड टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म) विकसित करेंगे, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे की सभी सेवाएं गैर-डिजिटल रूप से भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हों।
- हम झारखण्ड को देश के सभी मानव विकास के मापदंडों पर तेजी से आगे बढ़ाने एवं प्रदेश को शीर्ष के 5 प्रदेशों की श्रेणी में लाने की दिशा में निरंतर कार्य करेंगे।

नक्सली गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस

- ऑपरेशन समाधान के निरंतर कार्यान्वयन से एक आक्रामक रणनीति के साथ और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी नक्सली गतिविधियों के लिए कोई आर्थिक मदद ना हो, साथ ही झारखण्ड एक नक्सल मुक्त प्रदेश बनायेंगे।
- हम सशस्त्र/पुलिस कर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली पेंशन/क्षति-पूर्ति में वृद्धि करेंगे, जिन्होंने LWE क्षेत्रों में ड्यूटी पर रहते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है या स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदेश के वो युवा जो नक्सल गतिविधियों में शामिल हैं और आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, हम अपनी 'नई दिशा' नीति को और मजबूत करेंगे और व्यक्तिगत मामलों में पुनर्वास सिफारिशों के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।
- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि LWE क्षेत्रों में स्थित सभी पुलिस इकाइयां अत्याधुनिक तकनीकी सहायता से लैस हो।

जन-भागीदारी से जन-जन तक संपर्क

- हम प्रदेश में अनुपालन में लायी जाने वाली हर नीति, योजना, अधिनियम इत्यादि पर जनता के सुझावों को संलग्न करेंगे। हम जन-भागीदारी के सिद्धांत पर चलते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न माध्यमों से जन-जन के सुझावों एवं महत्वाकांक्षाओं को आधार मानते हुए ही नीति निर्माण किया जाए।
- हम प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत संचालित जन संवाद केंद्र का विस्तार करेंगे और तकनीक का उपयोग , उसका प्रचार-प्रसार कर जनता की हर शिकायत का शीघ्रता से निवारण करेंगे।
- हम प्रत्येक महीने बारी-बारी से झारखण्ड के प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी के अंतर्गत मुख्यमंत्री जन संवाद का आयोजन करेंगे और उसमें झारखण्ड की जनता द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का समयबद्ध निवारण करेंगे । प्रशासनिक जवाबदेही को समयबद्ध बनाकर, हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अकारण विलम्ब को समाप्त किया जाए।

पुलिस बल को सशक्त बनाना

- हम पुलिस बल में सभी रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरेंगे।
- हम पुलिस इकाइयों के यातायात विभाग के कर्मियों की संख्या बढ़ाएंगे, जो प्रदेश में बेहतर यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करेगा।
- हम प्रदेश भर में पुलिस स्टेशनों की संख्या को बढ़ाएंगे।
- हम प्रत्येक पुलिस स्टेशन, पुलिस नियंत्रण कक्ष और पुलिस मुख्यालय को अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे, आधुनिक और अग्रिम तकनीकी सहायता और प्रशिक्षित जनशक्ति से लैस करेंगे, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
- हम राज्य में स्थापित फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला को उच्च तकनीक से लैस कर सुदृढ़ करेंगे।
- हम राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के समन्वय से राँची में एक फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना करेंगे।
- हम प्रदेश में दो नए पुलिस प्रशिक्षण अकादमी बनाएंगे ,जो आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण प्रणालियों और विनिमय कार्यक्रमों से लैस होंगे।
- हम पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए एकीकृत पुलिस आवास परिसरों का निर्माण करेंगे। इन हाउसिंग इकाइयों में स्कूल, डे-केयर सेंटर, अस्पताल/क्लीनिक, स्पोर्ट्स सेंटर, छोटे बाज़ार, ट्रांसपोर्ट सुविधा, कल्याण केंद्र आदि होंगे।

न्यायिक सुधार

- हम निचली न्यायपालिका में सभी रिक्तियों को समयबद्ध रूप से भरेंगे एवं न्यायपालिका में महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजातियों के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे।
- हम राज्य में महिलाओं और वंचित समुदायों के खिलाफ हिंसा के मामलों को देखने के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या में वृद्धि करेंगे।
- सभी अदालती रिकॉर्डों को डिजिटल किया जाएगा और न्यायपालिका के सभी स्तरों पर ई-कोर्ट प्रणाली को अपनाया जाएगा।
- वर्तमान में क्रियान्वित पहल पर हम राज्य के कानूनों का मूल्यांकन करेंगे और अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर कानूनों-नियमों को सरल बनाने का का कार्य करेंगे।

स्वस्थ झारखंड

सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

- वर्ष 2020 तक हम झारखण्ड में सभी सुयोग्य श्रेणी के लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वर्ण स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क उपचार प्राप्त होगा। इस योजना को हम झारखण्ड में व्यापक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में विकसित करेंगे।
- हम आयुष्मान भारत योजना का उचित तरीके से कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जिला स्तरीय एजेंसियों की स्थापना करेंगे।

दवाएं और चिकित्सा उपकरण की सुगम पहुँच

- घरेलू स्तर पर थोक दवाओं के उत्पादों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए राज्य में फार्मास्युटिकल उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे।
- हम सभी सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं और दवा के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का विस्तार करके फार्मास्यूटिकल्स पर होने वाले खर्च को कम करेंगे।
- सस्ती दवाओं की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए मिनी जन औषधि स्टोर खोलेंगे।
- हम सभी शहरी केंद्रों में अटल मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या को दोगुना करेंगे।
- हम चिकित्सा उपकरणों जैसे पेसमेकर, स्टेंट्स और इम्प्लांट इत्यादि के लिए सब्सिडी देंगे और सरकार के द्वारा संचालित चिकित्सा और दवा की आपूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करेंगे।

हेल्थकेयर को सुलभ बनाना

- भाजपा सरकार ने देवघर में एम्स, पलामू, हजारीबाग और दुमका में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कर उसे चालू किया है, इसे अगले एक वर्ष में हर प्रकार से समृद्ध करेंगे।
- हम सभी जिला अस्पतालों को मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों में अपग्रेड करेंगे और साथ ही, लोगों को आवश्यक सब्सिडी वाली नैदानिक सेवाएं (डायग्नोस्टिक सर्विस) प्रदान करने के लिए सभी जिला अस्पतालों में पूर्ण सेवा नैदानिक प्रयोगशाला (लैब्स) की स्थापना करेंगे।
- हमारी सरकार सभी ज़िला अस्पतालों में प्रबंधकीय व्यवस्था को चिकित्सा सेवा से अलग करते हुए आधुनिक प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
- हम प्रदेश भर में वांछित संख्या में नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेंगे।
- हम सभी स्वास्थ्य उप-केंद्रों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में अपग्रेड करेंगे, जो टेलीमेडिसिन सेवाओं से लैस होंगे और आवश्यकतानुसार, ऐसे नए सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।
- प्रदेश भर में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, हम पूर्व से स्थापित सीएचसी को सुदृढ़ करते हुए 55 नए सीएचसी स्थापित करेंगे। इसके अलावा, जनजातीय क्षेत्रों में अतिरिक्त पांच सीएचसी स्थापित करेंगे।
- प्रदेश के आपातकालीन चिकित्सा वाहनों के बेड़े में 100 नई '108 एंबुलेंस' को जोड़ा जाएगा।
- हम सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करेंगे:
  - मोतियाबिंद, एचआईवी और कैंसर का पता लगाने के लिए प्रखंड स्तर पर त्रैमासिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन
  - टीबी, वेक्टर जनित, कुष्ठ रोग के साथ-साथ जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के लिए जागरूकता, रोकथाम और शुरुआती जांच के लिए स्वास्थ्य अभियान का शुभारंभ
  - आंगनवाडी केंद्र में बच्चों के लिए लगातार स्वास्थ्य जांच का आयोजन
- हम ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में काम कर रहे सभी डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स (चिकित्सा पेशेवरों) को आवास परिसर उपलब्ध कराएंगे और प्रत्येक प्रखंड में नर्सिंग क्वार्टर बनाएंगे।
- हम बाइक एम्बुलेंस सेवाओं के विस्तार के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करेंगे और राज्य के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करेंगे।

विशेष स्वास्थ्य सेवाएं और मूलभूत सुविधाएं

- हम मेडिकल हब के रूप में रांची में एक हेल्थ पार्क की स्थापना करेंगे और साथ ही साथ, हेल्थकेयर सेवाओं के तहत उपयोग होने वाले चिकित्सीय उपकरण की आपूर्ति का विनिर्माण भी करेंगे।
- सभी 5 प्रमंडलों के प्रमुख अस्पतालों में सस्ते कैंसर उपचार के लिए आधुनिक अटल कैंसर उपचार केंद्र स्थापित करेंगे।
- हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर जिले में मरीजों के लिए कम से कम एक डायलिसिस यूनिट उपलब्ध हो।
- हम सुनिश्चित करेंगे कि आपातकालीन मामलों के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पताल में एक ट्रॉमा सेंटर हो।
- हम सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करेंगे।

स्वास्थ्य सेवा में सुधार

- हम विशिष्ट स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर एक स्वास्थ्य संस्थान के अच्छे प्रदर्शन के लिए एक अवार्ड प्रणाली को संस्थागत बनाने की दिशा में स्टेट प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ़ हेल्थकेयर की शुरुआत करेंगे।
- हम विशेष रूप से अपेक्षित बुनियादी ढाँचे और जनशक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए एनआरएचएम मानदंडों को पूरा करने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना करेंगे।
- हम राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के सभी रिक्त पदों पर बहाली करेंगे, जिनमें डॉक्टर, नर्स और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं।
- हमारी सरकार सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टरों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएगी।
- हम नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के स्किल को बढ़ाने के लिए हेल्थकेयर अपस्किलिंग पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।
- डायरिया की रोकथाम के लिए एक राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे और ओआरएस के उपयोग के बारे में बताते हुए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- महिलाओं में आयरन की कमी, एनीमिया को कम करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेंगे और आयरन और विटामिन 'ए' सप्लीमेंट और रक्तदान सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे।
- आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य एवं कल्याण और अन्य चिकित्सा संस्थान की जानकारी के लिए एम स्वास्थ्य एप्लिकेशन लॉन्च करेंगे, जिसमें इससे जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। इसका इस्तेमाल फ्लू वायरस जैसी मौसम से जुड़ी बीमारियों और आवधिक अपडेट एवं रोकथाम की जानकारी के लिए किया जा सकेगा।
- हम प्रदेश में डॉक्टरों के लिए एक डबल रेसिडेंसी मॉडल की सुविधा प्रदान करेंगे। डॉक्टर जहां तैनात हैं, वहां उनके निकटतम बड़े शहर और दूरस्थ क्षेत्रों में भी रहने का विकल्प उपलब्ध कराएंगे।
- हम जिला खनिज निधि के उपयोग के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में संविदा डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे।

पारंपरिक चिकित्सा पद्धति

- हम प्रत्येक प्रमण्डल में एक आयुष महाविद्यालय की स्थापना करेंगे।
- जिला अस्पतालों के साथ साथ सभी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में आयुष सेवाएं सुनिश्चित करेंगे।

अनुसंधान को बढ़ावा देना

- हम आवश्यक नई जानकारी वाले क्षेत्र को कारगर बनाने के लिए एक व्यापक शोध एजेंडा विकसित करने और राज्य स्वास्थ्य नीति, योजनाओं और कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करने के लिए राज्य स्वास्थ्य सलाहकार समिति का गठन करेंगे।
- हम झारखण्ड में एक एकेडमिक एंड जेनेटिक डिजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे, जिसमें नजरअंदाज कर दी जाने वाली बीमारियां और उभरते संक्रमण के साथ उच्च प्राथमिकता के रोगों के लिए अनुसंधान की व्यवस्था करना शामिल होगा।
- हम स्वास्थ्य दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों जैसे जैव चिकित्सा विज्ञान, 3 डी प्रिंटिंग तकनीक, सस्ती नई दवाओं, टीकों आदि की खोज को प्रोत्साहित करेंगे।
- हम जनजातियों की जीवन शैली के अध्ययन और उनके इलाज के लिए राज्य में एक जनजातीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थापित करेंगे। हम इसमें अध्ययन के आधार पर, एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम तैयार करेंगे तथा जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे।

शिक्षित झारखण्ड,विकसित झारखण्ड

शिक्षा के लिए सशक्त बुनियादी ढाँचा

- हम 1,000 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष बनाकर सरकारी स्वामित्व के स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की सुविधा विकसित करने और उसका आधुनिकीकरण करने का वादा करते हैं।
- हम प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेंगे।
- हम सरकारी स्कूलों में छठी से बारहवीं तक की कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में बदलने के लिए विद्यालयों को स्मार्ट उपकरण प्रदान करेंगे, जिस पर उपलब्ध शिक्षा सामग्री का प्रयोग कक्षाओं में हो सकेगा।
- हम हर माध्यमिक विद्यालय में एक भाषा एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करेंगे, जिससे बेहतर शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे।
- हम हर प्रखंड में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना करेंगे। इस आदर्श विद्यालय को लर्निंग आउटकम्स, GER, अध्यापक - विद्यार्थी अनुपात, क्लास रूम - विद्यार्थी अनुपात, और आधुनिक बुनियादी ढांचों जैसे शिक्षा सम्बंधित मानदंडों में उत्कृष्ट बनाकर प्रखंड में स्थित अन्य स्कूलों के लिए उदाहरण पेश करेंगे।

सभी का अधिकार : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

- हम राज्य के शिक्षा दर को 2022 तक 90 प्रतिशत तक ले जाने के लिए कृत संकल्पित है।
- हम 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट (RTE) को सख्ती से लागू करेंगे और बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों से जो स्कूल ज़्यादा पैसे लेते हैं, उन के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे।
- हमारी सरकार प्राथमिक शिक्षा विकास के लिए "अपनी बोली" में पठन-पाठन को प्रश्रय देगी।
- इसके अलावा, झारखण्ड के विद्यार्थियों को प्रदेश और प्रदेश के बाहर फायदा मिल सके, इसके लिए उन्हें कक्षा 1 से हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान की जा रही है, हम इसे और विस्तारित कर प्रभावी बनायेंगे।
- हम हिंदी और अंग्रेंजी के साथ बुनियादी गणित में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, तीसरी से नौवीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए 3 महीने का ब्रिज कोर्स शुरू करेंगे।
- हम सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को दी जाने वाली कंप्यूटर की शिक्षा को और विस्तारित एवं प्रभावी बनायेंगे।
- हम कला, संगीत, नृत्य और खेल को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रत्येक सरकारी स्कूलों को झारखण्ड विद्यालय महोत्सव आयोजित करने का निर्देश दिया जाएगा जिससे सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके।
- हमारी सरकार ने शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की विद्यालय तक पहुँच एवं शून्य ड्रॉप आउट के साथ प्राथमिक शिक्षा से स्नातकोत्तर तक ढांचागत संसाधन एवं शैक्षिक परिवेश की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी सरकार हर स्तर पर शिक्षकों की कमी को एक वर्ष में पूरा करेगी।
- हमारी सरकार + 2 स्तरीय विद्यालयों एवं उच्चतर शिक्षा को निजी क्षेत्र एवं विशेषज्ञों के कौशल सहयोग से तकनीक युक्त बनाकर स्वावलम्बन की ओर विद्यार्थियों को प्रवृत करेगी।
- हमारी सरकार जहां विश्वविद्यालयों में शैक्षिक उन्नयन के सम्यक परिवेश निर्माण में विशेषज्ञों की सहायता से आगे बढ़ रही है, वहीं निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की गुणवत्ता की समीक्षा भी कराएगी।

विद्यार्थियों के कल्याण को सुनिश्चित करना

- हमारी सरकार केजी से पीजी तक आवश्यक संसाधन, उपकरण शैक्षिक संस्थाओं को समय पर उपलब्ध कराएगी।
- हमारी सरकार सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक और यूनिफार्म प्रदान कर रही है, साथ ही 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से साइकिल की भी सुविधा प्रदान कर रही है। हम इन कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाएंगे।

- रांची एवं दुमका में राज्य स्तरीय पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी जो सभी अत्याधुनिक सुविधा से संपन्न हो और इन्हें जिला विश्वविद्यालयों से लिंक किया जायेगा।
- झारखण्ड के जिन विद्यार्थियों ने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ काम करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को काम करने का मौका देने के लिए 'मुख्यमंत्री युवा फ़ेलोशिप' कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
- हम 'अडॉप्ट ए स्कूल' कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसके तहत झारखण्ड के लोग विद्यालयों को गोद लेकर उनके बुनियादी ढाँचे के विकास और शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के कल्याण कार्य में भाग ले सकते हैं।
- स्कूलों में पाठ्यक्रम, नए स्कूलों की आवश्यकता जैसे शिक्षा संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए झारखण्ड शिक्षा विशेषज्ञ परिषद की स्थापना करेंगे।
- हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम प्रदेश के भीतर और बाहर उद्योग के अनुभव और वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करने के लिए स्कूल भ्रमण यात्राएं आयोजित करेंगे।
- हम दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए आवश्यकता अनुसार मिनी बस सेवाओं की व्यवस्था करेंगे।
- हम यह सुनिश्चित करने के लिए 6 वीं कक्षा से शुरू होने वाले स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो, 6 वीं कक्षा से सभी स्कूलों में स्किलिंग अवधि को अनिवार्य बनाया जाएगा।
- हम झारखण्ड के सभी सरकारी स्कूलों में सब्जी बागानों के विकास को प्रोत्साहित करेंगे। उत्पादित सब्जियों का उपयोग बच्चों के मध्याह्न भोजन बनाने में किया जाएगा।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना

- हमारी सरकार की मंशा है कि प्रति वर्ष उच्च/उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अधिकतम नामांकन हो सके। सम्प्रति यह 19 प्रतिशत के लगभग है, हमारा संकल्प है कि वर्ष 2022-23 तक यह औसत 25 प्रतिशत तक हो जाए।
- सरकार के द्वारा मंजूर किए गए 52 डिग्री कॉलेजों के निर्माण में तेजी लाएंगे।
- हम विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का ढांचागत एवं शैक्षणिक कार्य पूरा करने के लिए उसमें तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे।
- हमारी सरकार ने अल्प अवधि में 5 विश्वविद्यालय, 5 अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित किए हैं, वहीं अगले 3 वर्षों में आवश्यकता अनुसार और अभियंत्रण कॉलेज, पॉलिटेकनिक, कौशल विकास तकनीकी संस्थान (निजी क्षेत्र में भी) खोले जाएंगे।
- महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को तकनीक आधारित शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी।
- सभी कॉलेज/विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक डिजिटल प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे।
- हम प्रदेश में झारखण्ड पत्रकारिता संस्थान का निर्माण करेंगे जिससे यहाँ के युवाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदेश में ही बेहतर शिक्षा एवं शोध के अवसर प्राप्त हो पाए।
- झारखण्ड चांसलर पोर्टल को और सशक्त किया जायेगा, जिससे झारखण्ड के विद्यार्थियों को प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉलेजों की जानकारी मिल सके।
- झारखण्ड के प्रत्येक विद्यार्थी को सुलभ शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम एक विशेष टास्क फ़ोर्स का गठन करेंगे जो शिक्षा ऋण की विधि को और सरल बनाने की दिशा में कार्य करेगी।
- इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए हम निजी कोंचिंग सेटरों के साथ काम करेंगे।
- हम प्रदेश के सभी जिलों में कैरियर काउंसलिंग सेल स्थापित करेंगे। ये विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के आधार पर भविष्य में करियर चुनने में मदद करेगी।
- हम झारखण्ड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ओपन पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
- हमारी सरकार मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत 5 साल तक पीएचडी शोधकर्ताओं को प्रति माह 15,000 रुपये प्रदान कर रही है। हम इस योजना के अंतर्गत अधिक के अधिक शोधकर्ताओं को लाभान्वित करेंगे।
- समाज के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को सस्ती उच्च शिक्षा मिल सके, इसके लिए, हम 'झारखण्ड स्कूल और कॉलेज फीस रेग्यूलेशन अथॉरिटी' की स्थापना करेंगे।

शिक्षक कल्याण सुनिश्चित करना

- हम सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली करने के लिए टास्क फोर्स का गठन करेंगे।
- प्रदेश के शिक्षा विभाग के तहत पेशेवर शिक्षकों की सीधी भर्ती सुनिश्चित करेंगे, जिससे उन्हें सभी प्रकार का लाभ मिल सके।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए हम प्रदेश के प्रत्येक जिले में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का गठन करेंगे। प्रशिक्षण में आईसीटी के उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएँगी।
- हम हर स्कूल में सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले शिक्षक को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करेंगे।
- भाजपा सरकार द्वारा पारा शिक्षकों के प्रति हमेशा से ही सरलता एवं सुगमतापूर्ण नियोजन की प्रक्रिया अपनायी गई है। पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनके लिए हमारी सरकार ने कई कल्याणकारी कार्य किये हैं एवं नियोजन के सम्बन्ध में नियमावली का प्रारूप तैयार किया गया है जिस पर आम सुझाव की मांग की गई है। हमारी सरकार बिना विलम्ब के प्राप्त सभी सुझाओं पर विचार करते हुए नियमावली बना कर नियोजन की प्रक्रिया शुरू करेगी।

“शिक्षा से ही समाप्त होगी गरीबी”

- श्री रघुवर दास

हमारी संस्कृति और धरोहर

भाषायी समृद्धि

- हमारी सरकार राज्य की समस्त भाषाओँ और साहित्यिक समृद्धि के लिए एक भाषा अकादमी का गठन करेगी, जिसमें शोध, संवाद और सृजन की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।
- झारखण्ड की जनजातीय और अन्य स्थानीय भाषाओं की मौखिक और लिखित साहित्य को डिजिटलाइज करके एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे।
- इतिहास, साहित्य और विज्ञान के उत्कृष्ट पुस्तकों को झारखण्ड के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवाएंगे।
- हम झारखण्ड के मूल जनजातीय और गैर-जनजातीय भाषाओं में बनी फिल्मों को आवश्यक धनराशि और बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड फिल्म निगम को सशक्त बनायेंगे।
- झारखण्ड की चौदह स्थानीय भाषाओं को जेपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन सेवा आयोग द्वारा होने वाली भर्तियों में स्थान दिया जायेगा।

झारखण्ड के शूरवीरों को नमन

- झारखण्ड को अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष का एक लम्बा सिलसिला रहा है। हमने चिन्हीतिकरण आयोग के माध्यम से अनुशंसित सभी आन्दोलनकारियों को सम्मानित करते हुए, 3,000/2,000 रुपये पेंशन और प्रशस्तिपत्र दिया है।
- हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास में पहली बार 2014 के स्वतंत्रा दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया था। हम उन आप्त वाक्यों का सम्मान करते हुए शहीद स्मारक पार्क बना कर भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ, सभी शहीदों की मूर्ति स्थापित करेंगे।
- नवरत्नग्रह फोर्ट कॉम्प्लेक्स और पलामू ट्विन फोर्ट कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण करेंगे।
- हमारी सरकार शहीद ग्राम योजना के अंतर्गत झारखण्ड के वीरों के गाँव के सर्वांगीण विकास की दिशा में कालबद्ध तरीके से कार्य करेगी।
- झारखण्ड के वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए :
  - राजा श्री रघुनाथ शाह की वीरता की याद में नवरत्नग्रह किला परिसर में उनकी प्रतिमा लगवाएंगे
  - राजा मेदिनी राय की वीरता और चेरो साम्राज्य की याद में पलामू किले में उनकी प्रतिमा लगायी जाएगी
  - झारखण्ड आंदोलन के वीरों और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रांची में हम एक स्मारक और संग्रहालय का निर्माण करेंगे
  - लोहरदगा में ठाकुर विश्वनाथ शाह की एक प्रतिमा स्थापित करेंगे और झारखण्ड में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के शूरवीरों के लिए एक स्मारक का निर्माण करेंगे

प्रदेश के जनजातीय समुदायों का सांस्कृतिक विकास

- प्रदेश के जनजातीय और अन्य स्वदेशी संस्कृतियों के संरक्षण और उत्थान के लिए कार्तिक उरांव के नाम पर एक विकास कोष बनाएंगे।
- झारखण्ड के जनजातीय समुदायों के अंतर्गत बनी हुई सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझने और सुलझाने के लिए हम एक विशेष प्रयास करेंगे।

सांस्कृतिक - सामाजिक सद्भाव एवं समन्वय

- हम झारखण्ड फ्रीडम ऑफ़ रिलिजन एक्ट, 2017 को सख्ती से क्रियान्वित करेंगे ताकि समाज के कमजोर वर्गों में जबरन धर्मान्तरण पर पूरी रोक लगायी जा सके।
- प्रदेश में, ख़ास कर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में काम कर रही सभी एनजीओ की समीक्षा करेंगे और उनके संचालन पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि प्रदेश की संस्कृति, सामाजिक सद्भावना और सुरक्षा को कोई ठेस नहीं पहुंचे।

प्रदेश की धार्मिक विरासतों का नवीनीकरण

- बैद्यनाथ मंदिर (देवघर), बिंदुधाम (बरहरवा), मलूटी मंदिर (मलूटी), जगन्नाथ मंदिर (रांची), छिन्नमस्तिका मंदिर (रामगढ़), हरिहर धाम (गिरिडीह), देवरी मंदिर (रांची), नौलखा मंदिर (देवघर) जैसे प्रमुख मंदिरों के झारखण्ड स्टेट बोर्ड ऑफ़ रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा रखरखाव और नवीनीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
- प्रदेश भर में जनजातियों के प्रमुख धार्मिक स्थलों और परंपराओं की पहचान करने के लिए एक समिति की नियुक्ति करेंगे, जिन्हें सरकार और झारखण्ड स्टेट बोर्ड ऑफ़ रिलीजियस ट्रस्ट के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- प्रदेश भर में प्रमुख धार्मिक/सामाजिक सांस्कृतिक मेलों की पहचान करने हेतु अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ, हम इन मेलों को भव्य तरीके से संचालित करने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान करेंगे।
- सरहुल, मेज पर्व, हाल पुन्ह्या और भगत पर्व समेत हम झारखण्ड के त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और उन्हें झारखण्ड की संस्कृति के रूप में देश के साथ दुनिया के बाकी हिस्सों में प्रदर्शित करेंगे।

कला, नृत्य एवं हस्तशिल्प का संरक्षण और संवर्धन

- झारखण्ड अपनी कलात्मक ललित संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहां डोकरा आर्ट, बांस हस्तशिल्प, काष्ठकला, माटी कला, पत्थर पर खुदाई होती हैं। रेशम के कलात्मक उत्पाद, जादुपटिया, बादोनी आदि प्रसिद्ध है। पेंटिंग में कोहबर, सोहराई, पैतकर सहित अनेक ग्रामीण पद्धति प्रसिद्ध हैं।
- हमारी सरकार मधुबनी पेंटिंग की तरह इसे विश्व बाजार में विज्ञापित करेगी एवं कलाकारों को दक्षता के आधार पर पुरस्कृत करेगी, साथ ही इस कला के प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करेगी।
- जनजातीय कला विशेषकर कोहवर और सोहराई चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए रांची में अनुसंधान संस्थान की शुरूआत करेंगे, जिसमें विभिन्न परंपराएं शामिल होंगी। इस संस्थान के माध्यम से हम झारखण्ड सरकार और भारत सरकार के प्रमुख भवनों की आंतरिक सजावट कराएंगे।
- झारखण्ड के प्राकृतिक प्रागंण में सदा संगीत-नृत्य का संगम रहता है। बताया जाता है कि यहां 80 प्रकार के नृत्य होते हैं, जिनमें भारतीय नाटय शास्त्र आधारित सरायकेला का छऊ विश्व प्रसिद्ध है। प्रकृति अर्थात मौसम और अन्न के फसली मौसम के अनुसार इनका संयोजन होता है।
- हम झारखण्ड की लोक नृत्य परंपराओं को संस्थागत बनाने, संरक्षित करने के लिए लोक नृत्य संस्थान का गठन करेंगे। इससे मुंडारी, संथाली, कुरुख, छऊ, पईका, लोक नागपुरी इत्यादि को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।
- हम झारखण्ड की संगीत परंपराओं- झूमर, डोमकच और हिंदुस्तानी संगीत को झारखण्ड के भीतर संस्थागत रूप देने और बढ़ावा देने के लिए झारखण्ड संगीत कला अकादमी बनाएंगे।
- हमारी सरकार यथाशीघ्र समस्त कला-कौशल, नृत्य-संगीत, पेंटिंग आदि के विस्तार, बाजार तक पहुँच, कलाकारों की जीवन-जीविका के लिए दो वर्षो में यथेष्ठ व्यवस्था करेगी।
- हस्तशिल्प और हस्तकला में, इस राज्य की तुलना पूर्वांचल के राज्यों से ही की जा सकती है। शिल्प हस्तकला प्रकृति के स्कूल से ही समवेत होता है। टेसू के रंग, मौलश्री और सेमल, छितवन के सुगन्ध मिश्रित कला के अनुपम लालित्य का उपयोग किया जाएगा।
- डोकरा, मुखौटा, ब्रास मेटल के काम, जूट क्राफ्ट, खिलौने, चटाई, बांस के शिल्प, सबसे बढकर रेशम उत्पाद परम्परा में रहे-बसे हैं। अतः हमारी सरकार इन्हें संस्थागत स्वरूप देगी और सभी शिल्प तथा हस्तशिल्प को प्रशिक्षण आधारित विकसित करेगी।

गौ संरक्षण

- हमारी सरकार जिन गोवंशीय पशुओं की उत्पादक क्षमता खत्म हो गयी हो, उन पशुओं के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष गोशालाओं का निर्माण कराएगी।

पर्यटन का विकास

बुनियादी ढांचे का विकास

- प्रकृति ने झारखण्ड को पर्यटन हेतु अतुल्य पारिस्थितिकी एवं परिवेश उपलब्ध कराया है। सुरम्य घाटियों, वन प्रांत, कल-कल बहती नदियाँ, अभयारण्य, वन्य पशु प्रांगण, पक्षी विहार के साथ-साथ पुरातन वस्तु यहां तक की फोसिल्स पार्क, वनवासी सभ्यता संस्कृति, राष्ट्रीय धरोहर, शहीदों की स्तुत्य भूमि, विराट औद्योगिक प्रांगण, भाषा-बोली के साथ विविध प्राकृतिक उपादेन राज्य में पर्यटन के लिए चित्राकर्षण परिवेश का निर्माण करते है। ये सरकार की पहल का परिणाम है कि पर्यटकों के आगमन में तेज वृद्धि हो रही है। झारखण्ड में आज 1 लाख 75 हज़ार विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, यह हमारी पर्यटन क्षेत्र में किये गए कार्यों का परिणाम है।
- हम विश्व स्तरीय पर्यटन संरचना बनाने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करेंगे। इस बजट का इस्तेमाल अगले पांच वर्षो में होटल, पार्क, राजमार्ग, हेलीपैड, शौचालय, मनोरंजन पार्क बनाने के लिए किया जाएगा।
- हम स्वच्छ और बजट सरकारी होस्टल्स स्थापित करके अकेले (सोलो) यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा और ठहरने की सुविधा प्रदान करेंगे।
- हम झारखण्ड को पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर हम 24 घंटे और सातों दिन पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित करेंगे।
- हमारी सरकार अगले 5 वर्षों में पर्यटन एवं पर्यटन ढांचागत विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगी।
- पर्यटन विकास के लिए सी.एस.आर एवं पी.पी.पी. मोड के तहत सहभागिता में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा, एक सौ करोड़ का एक कॉर्पस फंड व्यवस्थित करेंगे, जिससे पर्यटन विकास में कठिनाई न हो।

सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा

- हम झारखण्ड के तीन राजकीय मेलों - राजकीय जनजातीय हिजला मेला, देवघर श्रावणी मेला और कांवरिया मेला - का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम हर साल कर्मा पूजा के समय तीन दिन का 'झारखण्ड पर्व' आयोजित करेंगे। इस पर्व के माध्यम से झारखण्ड के लोकगीत, संगीत, नृत्य, कला और राज्य के व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- हम जल्द ही दुमका जिले के मालुती मंदिरों के संरक्षण और नवीनीकरण का काम करेंगे और हर वर्ष इन मंदिरों के इतिहास को दर्शाते हुए 'मलुटी महोत्सव' का आयोजन करेंगे।
- 'उलगुलान आंदोलन' के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा के संघर्षों की याद में 'धरती आबा टॉवर' का निर्माण करेंगे।
- हमारी सरकार राज्य व्यापी पर्यटन विकास के लिये राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाएगी।
- धार्मिक पर्यटन के लिए यथा आवश्यक ढांचागत निर्माण, सुरक्षा, परिवहन, बाजार की समुचित व्यवस्था के अतिरिक्त समुन्नत व्यवस्था करेगी। सरकार का यह प्रयास होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल को पी.पी.पी. मोड में वैश्विक स्तर पर विकसित किया जाए। यहां स्थानीय एवं देश-विदेश के पर्यटकों के लिए व्यवस्था की जाएगी।
- देवघर बाबा बैधनाथ की कृपा से श्रावण माह में विशेष और अन्य महीनों में सामान्यतः पर्यटकों के आगमन की निरंतरता बनी रहती है, सरकार यहां (देवघर-बासुकीनाथ) के लिए आवास, परिवहन, सुरक्षा, खान-पान, चिकित्सा आदि की यथेष्ट उच्चतम व्यवस्था करेगी।
- राजमहल में गंगा किनारे पुरातात्विक धरोहर मुगलकाल के ऐतिहासिक वैभव से भरे पड़े हैं तथा चैतन्य महाप्रभु का मंदिर, पक्षी विहार (उधवा), फोसिल्स पार्क को पर्यटन सुविधाओं से सवंर्द्धित किया जाएगा। इसी प्रकार, गुफा पेंटिंग, मेगालिथिक मोनुमेट्स, बेनीसागर, हरडीह के मंदिरों, राँची के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जामा मस्जिद, नवरत्नगढ़, जी.ई.एल. चर्च के साथ-साथ पलामू किला जैसे पर्यटक स्थलों को भी विकसित करेंगे।
- नेतरहाट, बेतला, विशुनपुर, खुँटी के मृग विहार सभी आश्रणियों को सभी सुविधाओं से लैस करेंगे।

- प्रदेश के गढ़वा में भगवान वंशीधर का पुरातन और महत्वपूर्ण मंदिर हैं। उसे पर्यटकों के लिए आकर्षित बनायेंगे।
- इसी प्रकार, रजरप्पा, देउड़ी, भद्रकाली को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक क्षेत्र के रूप में यथाशीघ्र विकसित करेंगे।
- संथाल परगना, राँची, पलामू एवं अन्य स्थानों से सम्बद्ध सरकारी संस्थाओं/शैक्षिक संस्थानों आदि का नामकरण शहीदों के नाम कर उसे पर्यटन विकास से जोड़ेंगे।
- सूर्य मंदिर, पतरातू घाटी एवं अन्य दर्शनीय स्थलों को भी पर्यटकों के लिए पहुंच योग्य बनाएंगे।

झारखण्ड के पर्यटन का समग्र विकास

- हम भारत सरकार के स्वदेशी दर्शन पैटर्न पर प्रदेश में इको टुरिज्म सर्किट बनाएंगे। इसके तहत निम्न दलमा, चांडिल, गेतलसुद, बेतला, मिरचैया और नेतरहाट को इको टुरिज्म के लिए विकसित किया जायेगा।
- हम इको लॉग हट्स, क्राफ्ट हट्स, स्मारिक दुकानें, खुले एम्फीथिएटर्स और जनजातीय व्याख्यान केंद्र विकसित करने के लिए जनजातीय संस्कृति सर्किट को लांच करेंगे जो उनके इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करेंगी । जनजातीयकला से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
- हम 50 करोड़ की लागत से प्रदेश में नए एडवेंचर पर्यटन के स्थानों को विकसित करेंगे और हर साल मेगा थ्रिल कैंप का आयोजन करेंगे।
- हम राज्य में माइनिंग पर्यटन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माइनिंग पर्यटन का विकास हम कोल इंडिया के सहयोग से करेंगे और बंद हुए खदानों में पुनः वनरोपण पर भी ध्यान देंगे।
- हम इको-फ्रेंडली कैंपिंग साइटों की भी शुरूआत करेंगे जिसे क्षेत्र के युवा के द्वारा चलाया जाएगा। यह सामुदायिक इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा जहां स्थानीय समुदाय इको सेंसटिव जोन को संरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- हम प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित करेंगे। जेटीडीसी पर्यटन में विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा, जो 1950 से पहले बने बंगलों का पुनर्विकास करके उन्हें उच्च स्तर पर होटल बनाने का काम करेंगे।
- हम प्रदेश में वेलनेस पर्यटन के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करेंगे। प्रदेश में वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता और 33.21% वन क्षेत्र होने के साथ झारखण्ड वेलनेस पर्यटन का हब बन सकता है। इसके लिए हम विशेषज्ञ नियुक्त करेंगे जो योग और ध्यान केंद्रों, आयुर्वेदिक उपचार केंद्रों और विपश्यना केंद्रों को विकसित कर सकें।
- हमारी सरकार जैवीय गार्डन, हर्बल उत्पाद वाटिका, आरोग्य निकेतन प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के आसपास विकसित करेगी। सभी तीर्थ स्थलों पर आवागमन को सुगम, सुरक्षित एवं आकर्षित बनाएंगे।
- राँची नगर के आस-पास 13 पहाड़ियां है, जिन्हें पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाएंगे। इसी प्रकार, सभी जल-प्रपातों के पास पर्यटकों के लिए यथेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

पर्यटन उद्योग

- हमारी सरकार राज्य व्यापी पर्यटन विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाएगी।
- पर्यटन उद्यमियों को सस्ते दर पर ऋण और सीड कैपिटल उपलब्ध कराने हेतु योजना तैयार की जाएगी। इस फंड के द्वारा, केंद्र सरकार के होम स्टे योजना के सहयोग से उन स्थानीय उद्यमियों की भी मदद करेंगे जो झारखण्ड में होम स्टे चलाना चाहते हैं।
- हम टूर गाइड, टैक्सी ड्राइवर, होटल स्टाफ, लाइफगार्ड सहित अन्य लोगों को रोजगार देने के लिए झारखण्ड पर्यटन कौशल विकास कोष की स्थापना करेंगे। 2024 तक पर्यटन उद्योग में कार्यरत लोगों की संख्या को 5 लाख तक बढ़ाने का विचार है।
- हम पर्यटन के विकास के लिए प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को प्रोत्साहित करेंगे।
- 'पर्यटन परियोजना क्लीयरेंस बोर्ड' की स्थापना की जाएगी, जहां रांची, झारखण्ड में वन-स्टॉप क्लीयरेंस विंडो में पर्यटन व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी लाइसेंस और परमिट प्रदान किए जाएंगे।

- हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झारखण्ड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों के साथ जुड़कर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।
- हम 'चलो झारखण्ड' एप्प लॉन्च करेंगे ताकि झारखण्ड की संस्कृति और इतिहास के प्रचार से झारखण्ड में पर्यटन का विकास हो सके। इसके साथ-साथ पर्यटकों की सहायता के लिए हम एक 24/7 हेल्पलाइन भी शुरू करेंगे।
- हम प्रदेश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर वन-स्टॉप पर्यटन समाधान केंद्र स्थापित करेंगे।
- हमारी सरकार, इसी के साथ राज्य में स्थित पर्यटन को रोजगार का बड़ा अवसर बनाने के लिए सुरक्षा, परिवहन, कुरियर, गाइड, पर्यटन सूचना केन्द्र, होटल, आर्ट कल्चर सहित अनेक अवसरों को प्रोजेक्ट बनाकर पर्यटन सेवा वृद्धि करेगी।
- पर्यटन विकास निगम को प्रभावी बनाकर अपेक्षित साहित्य प्रकाशन, प्रदर्शिका, विज्ञापन, विविध आयोजन, महोत्सव आदि के माध्यम से पर्यटन विकास को बल देकर रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे।
- इस प्रकार, हमारी सरकार अगले 5 वर्षों में पर्यटन एवं पर्यटन ढांचागत विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगी।
- पर्यटन विकास के लिए सी.एस.आर एवं पी.पी.पी. मोड के तहत सहभागिता में वृद्धि करेंगे।

वन और पर्यावरण संरक्षण

हमारे जंगल हमारा भविष्य

- विगत पांच साल में हम ने प्रदेश में 33.21% फॉरेस्ट कवर का लक्ष्य प्राप्त किया है, इसे आगे 34% तक बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम फॉरेस्ट कवर में वेरी डेन्स फॉरेस्ट का भाग जो वर्तमान में 11.08% है उसे हम 13% तक बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं।
- हम एक 'केनोपी मेज़रमेंट इंडेक्स' स्थापित करेंगे, ताकि वन स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से माप सके।
- हम प्रदेश भर में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने और उच्च तकनीकी वाली बांस की नर्सरी स्थापित करने के लिए 'ग्रीन गोल्ड प्रमोशन मिशन' की शुरूआत करेंगे। साथ ही बांस आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे।
- हम प्रदेश के पूरे वन क्षेत्र को जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट समितियों के दायरे में लाएंगे, ताकि हमारी वन संपत्ति की सुरक्षा में स्थानीय समुदाय भी भागीदार बने। इन समुदायों को इसमें सक्षम बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं में आईईसी कार्यक्रम शुरू करेंगे।
- वन के विकास और संरक्षण के लिए हम हर जिले के लिए योजना बनाएंगे और उसे लागू भी करेंगे।
- हम वन और बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए GIS और जिओस्पेशियल टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। प्रदेश में वनों के विस्तार के लिए स्टेट कम्पेन्सेटरी अफ्फोरेस्टशन फंड के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेंगे।
- हम प्रदेश भर में वृक्षों के आवरण को बढ़ाने के लिए शहरी वनीकरण योजना शुरू करेंगे।
- जलवायु परिवर्तन के सभी पहलुओं के सक्षम प्रबंधन के लिए "स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज" के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संकल्पित है।
- हम वन प्रबंधन और संरक्षण को कम उम्र से ही नागरिकों की आदत बनाने के लिए वन प्रबंधन और वन संरक्षण को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।

वन्यजीव संरक्षण

- हम टाइगर कंजर्वेशन सेल और एलीफेंट कंजर्वेशन सेल की स्थापना करेंगे जिससे प्रदेश भर में अवैध शिकार की घटनाओं पर नज़र रखने के साथ-साथ बाघों और हाथियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके।
- हम वन्यजीव अपराध पर गंभीर रूप से कार्रवाई करेंगे और वन्य जीवों के अवैध शिकार और तस्करी को समाप्त करने के लिए अन्य राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।
- हम वन भूमि के अतिक्रमण को रोकेंगे ताकि जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में न आ पाए। नागरिकों को जंगली जानवरों से सुरक्षा और इससे प्रभावित लोगों को उपयुक्त मदद प्रदान करेंगे।
- हम अभयारण्य प्रबंधन योजना का मसौदा तैयार करेंगे और उसे प्रभावी ढंग से लागू करेंगे।

सतत विकास के माध्यम से हरित और स्वच्छ पर्यावरण

- प्रदेश के सभी शहरी केंद्रों में 24* 7 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी शहरों की परिवेशी वायु की गुणवत्ता अच्छी हो।
- हम सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने के लिए संकल्पित हैं।
- 2022 तक हम झारखण्ड को सिंगल-यूज़ प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हम 'उजाला योजना' को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे और स्ट्रीट लाइटों के साथ सभी सरकारी कार्यालयों में 2022 तक एलईडी लाइट लगवाएंगे।
- हम प्रदेश में 5 इको -सेंसिटिव स्थानों की पहचान कर, उन्हें विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान करेंगे।
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को सख्ती से लागू करेंगे और कूड़े के प्रबंधन को आसान और सक्षम बनाने के लिए उसे उद्योग के तौर पर विकसित करेंगे।

- हम रीसाइकल्ड उत्पादों के लिए क्रेडिट और मूल्य समर्थन के लिए नीतियां और तंत्र बनाएंगे।
- हम 50 करोड़ रुपये का झारखण्ड एन्वायरनमेंट इनोवेशन फंड बनाएंगे जिससे पर्यावरण से संबंधित शोधकों और स्टार्ट-अप को सहायता मिलेगी।
- हम प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) केंद्रों की स्थापना करेंगे और प्रदेश भर में मोबाइल वाहन उत्सर्जन परीक्षण वैन शुरू करने के साथ अगले पांच वर्षों में ऐसे सभी केंद्रों को ईंधन रिफिलिंग स्टेशनों के साथ सम्बद्ध करेंगे।
- हम सीएनजी और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 फीसदी छूट देने का वादा करते हैं और प्रदेश में इन वाहनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए निवेश करेंगे।
- औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले उत्सर्जन पर निगरानी रखने के लिए हम एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम (वास्तविक समय की निगरानी प्रणाली) और पोर्टल बनाएंगे।
- हम प्रदेश की किसी भी नदी में कोई भी अनुपचारित गंदा पानी न डाला जाए, ऐसा करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।
- हम प्रदेश में एक हर्बल नीति के साथ एक हर्बल विकास बोर्ड का गठन करेंगे और उनके विकास और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करके जड़ी-बूटियों और संबंधित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देंगे।
- हम आपदा प्रबंधन नीति को और मजबूत करेंगे जिसका विशेष ध्यान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने पर होगा।
- हम स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और उद्योगों से कम कार्बन उत्सर्जन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में एक समिति का गठन करेंगे।
- हम प्रदेश के सभी स्कूलों, महाविद्यालयों, कार्यालयों आदि को मिट्टी और जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देने के साथ द्विमासिक वृक्षारोपण अभियान चलाने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। हम विद्यार्थियों को प्रतिदिन कुछ समय निकालकर पेड़ों, बगीचों के रखरखाव और संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
- हम यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे कि सभी नागरिक प्रदेश की पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रति अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अवगत हों।

संकल्प पत्र समिति

श्री वी.डी.राम, सांसद
अध्यक्ष

श्री सुनील कुमार सिंह, सांसद
सदस्य

श्री रविन्द्र कुमार राय, पूर्व सांसद
सदस्य

श्री अयोध्यानाथ मिश्र,
पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार, सदस्य

श्री जे.बी.तुविद, पूर्व भा.प्र.से.
सदस्य

श्री अनिल सिन्हा
पूर्व महाधिवक्ता, सदस्य

श्री एस.के.मजुमदार
पूर्व महाधिवक्ता, सदस्य

NOTES

NOTES

भारतीय जनता पार्टी,
झारखण्ड प्रदेश

प्रकाशक:
भाजपा प्रदेश कार्यालय,
एम-7 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन,
हरमू रोड, रांची 834002

मुद्रक:
अन्नपूर्णा प्रिंटर्स5,
मेन रोड रांची 834001
संख्या: 500